04 - आठवें वेतन आयोग के गठन में इतना विलंब क्यों?

05 - विश्व धरोहरों का संरक्षण सांस्कृतिक जरूरत है

A Daily News Magazine

इंदौर

शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025

06 - जबलपुर में बिना अनुमति चल रहा हॉस्पिटल

07 - नवागत कलेक्टर ने की कृषि विभाग की समीक्षा

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 188, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

बरा ए शौक हमने चक्खा है
शराब ए इश्क़ में क्या रक्खा है
इक तेरे दीद की खातिर तो
हमने हथेली पे दम रक्खा है
कभी आओगे तुम चुकाओगे
हमने लिखकर उधार रक्खा है
तुम कि जिल्द से उधड़ते हो
हमने पन्नों को बॉध रक्खा है
जुलूस सड़कों को थर्राते हैं
हमने रुह में राम रक्खा है
खुदा इस हाल के लिए तूने
क्या मुझे बेनियाज़ रक्खा है
बेड़ियाँ बेचैन करतीं कैसे
उनने गहना मान रक्खा है
मुस्कराहट एक फरेब वहाँ
जिन्हें रहनुमा मान रक्खा है।।

– विवेक चतुर्वेदी

प्रसंगवश

तेलंगाना में लागू एससी सब कोटा बदलेगा देश की राजनीति?

पंकज श्रीवास्तव

तेलंगाना में लागू किया गया एससी सब-कोटा न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी नई दिशा दे सकता है। क्या यह सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से केंद्र में लाएगा?

तेलंगाना में सरकार ने 14 अप्रैल, 2025 को एक ऐतिहासिक क़दम उठाया। इस दिन, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी सब कोटा लागू करने की घोषणा की गई। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त, 2024 के फ़ैसले को इतनी तेजी से लागू किया। यह फ़ैसला न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा क़दम है, बल्कि यह कांग्रेस की नई रणनीति और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के बीच टकराव का भी संकेत देता है। यह मायावती जैसी नेताओं के लिए एक और चुनौती है जिन्होंने उपवर्गीकरण का विरोध किया है।

14 अप्रैल, 2025 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने वह गजट अधिसूचना सौंपी, जिसके तहत अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण में सब कोटा लागू हुआ। इसके तहत एससी की 59 उपजातियों को तीन वर्गों में बाँटा गया:

समूह-I: सबसे पिछड़ी 15 उपजातियों को 1% आरक्षण। ये जनसंख्या का 0.5% हैं।

समूह-II: 18 उपजातियों को 9% आरक्षण।

समूह-III: अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाली 26 उपजातियों को 5% आरक्षण।

2025 के तेलंगाना जाति सर्वे के अनुसार, राज्य की 3.7 करोड़ आबादी में एससी समुदाय 17.43% यानी क़रीब 61.84 लाख है। सबसे बड़ी उपजातियाँ मादिगा (50-55%) और माला (35-40%) हैं, जबकि रेली, मेडिगा, और बिंदला जैसी छोटी उपजातियाँ बाक़ी हिस्सा बनाती हैं। मादिगा समुदाय लंबे समय से शिकायत करता रहा है कि माला समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर है। माला समुदाय का कहना है कि वे भी पूरी तरह मुख्यधारा में नहीं आये हैं।

यह नीति उन उपजातियों को अवसर देगी, जो अब तक हाशिये पर थीं। लेकिन क्या इससे दलित एकता प्रभावित होगी? कुछ इसे सामाजिक न्याय का कदम मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि यह उन लोगों का विरोध है, जो 'रेल के डिब्बे में जगह पाकर दूसरों के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं।'

इस नीति का आधार सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त, 2024 का फ़ैसला है, जिसमें 7 जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से कहा कि राज्य SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इस बेंच में चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्त्य नटेश्वर, और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। यह फ़ैसला 2004 के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले को पलटता है, जिसमें SC को एक समरूप समूह मानकर उपवर्गीकरण को असंवैधानिक बताया गया था।

कोर्ट ने कहा कि उपवर्गीकरण से उन उपजातियों को न्याय मिलेगा, जो आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पाईं, बशर्ते ठोस डेटा और पारदर्शी प्रक्रिया हो। इसने पंजाब, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के पुराने उपवर्गीकरण कानूनों को भी वैधता दी।

तेलंगाना ने इस फैसले को आधार बनाकर 96.9% आबादी को कवर करने वाला जाति सर्वे कराया और उपवर्गीकरण लागू किया। सरकार ने यह भी वादा किया कि अगली जनगणना के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से 'जितनी आबादी, उतना हक' का नारा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संसाधन, नौकरियाँ, और अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए वे देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद में हाल के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने तेलंगाना के जाति सर्वे की तारीफ़ की और इसे सामाजिक न्याय का मॉडल बताया।

तेलंगाना का सब कोटा और जाति सर्वे इस दिशा में ठोस कदम है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य है, जिसने ऐसा सर्वे किया। कर्नाटक में भी 2015 की सामाजिक-आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 11 अप्रैल, 2025 को कैबिनेट में रखी गई, जिसके नतीजे जल्द सामने आ सकते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सामाजिक न्याय की नई चैंपियन बनकर उभर रही है। उनके संविधान सम्मेलनों और 'न्याय पथ' अभियान ने पार्टी को नए सामाजिक दायरे में ले जाना शुरू किया है।

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण फैसले का कड़ा विरोध किया था। 21 अगस्त, 2024 को उन्होंने इस फ़ैसले के खिलाफ हुए भारत बंद का समर्थन करते हुए इसे 'दलित एकता को तोड़ने की साजिश' बताया था। उनका मानना है कि उपवर्गीकरण से कुछ उपजातियों को लाभ होगा, लेकिन यह दलित समुदाय की एकजुटता को कमजोर करेगा।

मायावती के लिए यह दुविधा है। वह सिर्फ एक दलित उपजाति की नेता नहीं बनना चाहतीं, लेकिन उपवर्गीकरण का विरोध उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। यह सच है कि कुछ उपजातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला, जबकि अन्य पीछे रह गईं। ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से यह असमानता बनी, लेकिन मायावती का विरोध इस बदलाव को रोकने की कोशिश है।

कांग्रेस की यह रणनीति बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए चुनौती बन रही है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन इसे कराने से भी बचती रही है। बीजेपी के मंचों पर राहुल गांधी को 'हिंदुओं को जाति के आधार पर बाँटने वाला' बताया जाता है, जबकि पार्टी के नेता मुस्लिम विरोधी बयानबाजी कर ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, ताकि जाति जनगणना का सवाल दब जाए। बहरहाल, जिस विचार का समय आ जाता है, वह समाज में जगह बना ही लेता है। जाति जनगणना और आरक्षण का सवाल गरीबी उन्मूलन से ज़्यादा शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी का है। तेलंगाना का सब कोटा फ़ैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया अध्याय है। यह राहुल गांधी के 'जितनी आबादी, उतना हक' के नारे को मजबूती देता है और जाति जनगणना की मांग को नई हवा दे रहा है। लेकिन मायावती जैसे नेताओं का विरोध और बीजेपी की सियासी रणनीति इसे जटिल बनाते हैं। क्या यह फैसला देश की राजनीति को नया रंग देगा? क्या कांग्रेस सामाजिक न्याय की नई ध्वजवाहक बनेगी? इसका जवाब समय देगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह मुद्दा समाज और सियासत में गहरे बदलाव की शुरुआत कर चुका है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

केन्द्रीय मंत्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में 2026 तक देश होगा नक्सलवाद से मुक्त : शाह

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में वर्ष 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस प्रण को पूरा करने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जरूरत होती है, सीआरपीएफ के जवान सदैव कर्तव्य पथ पर तत्पर रहते हैं। देश का जब भी स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, उसमें सीआरपीएफ के शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 86 वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर परेड ग्राउंड नीमच में परेड का निरीक्षण भी किया।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह गुरुवार को नीमच स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिह, क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर सहित

जिले के तीनों विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के कर्मियों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने सीआरपीएफ की आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी गतिविधियों, शांति स्थापना के कार्यों में निभाई गई भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 'जहां सीआरपीएफ है, वहां चिंता करने की कोई बात नहीं'।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि आज सीआरपीएफ के 3 लाख जवान देश में कानून-व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश की संसद पर आतंकी हमले और श्रीराम जन्मभूमि पर हमले जैसी मुश्किल समय में कई बार सीआरपीएफ जवानों ने वीरता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान दिया।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सीएपीएफ कर्मियों को आयुष्मान कार्ड और आवास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सीआरपीएफ में अब महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। उनके लिये भी आवास सुविधा विकसित की जा रही है। सीआरपीएफ को आधुनिक बनाए रखने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से उत्कृष्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदर्शनी का अवलोकन किया

सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह की परेड के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सीआरपीएफ कैम्प नीमच के परिसर में ''राष्ट्र सेवा में समर्पित सीआरपीएफ के विभिन्न आयाम चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक फोर्स द्वारा अर्जित उपलब्धियों एवं विभिन्न गतिविधियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

उल्लेखनीय है कि 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड इस वर्ष 17 अप्रैल को विस्तारित समारोहों के अन्तर्गत आयोजित की गई। सामान्यत: सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज प्रदान किया था। इस वर्ष नीमच में आयोजन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासन के दौरान 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस' की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद, 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल ने इसे 'केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)' नाम दिया। आज सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है हर चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में डटे रहकर, 'सेवा और निष्ठा' के अपने मूल मंत्र को चरितार्थ कर रहा है।

वक्फ कानून: नई नियुक्ति पर 'सुप्रीम' रोक

● संपत्तियां पहले जैसी ही रहेंगी ● सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया फिलहाल कोई स्टे

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का वक्त दिया। वहीं

● केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दिया एक हफ्ते का वक्त

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर

कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली सुनवाई तक बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है। सीजेआई ने कुछ खास लोगों को 2013 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दी है। यह एक विशेष मामला है। सीजेआई ने कहा, याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। सभी को जल्द से जल्द जवाब देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता सिर्फ 5 याचिकाएं ही दें। सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह तीन मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट अभी कुछ समय के लिए ये नियम लागू करेगा। पहला मुद्दा वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है।

नड्डा की जगह कौन, पीएम आवास पर हुई अहम बैठक

● एक हफ्ते में हो सकता है फैसला, राज्यों के अध्यक्ष पर भी चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,

पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले दो-तीन दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी, 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी, 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। एक नेता ने कहा-जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन गई हैं सीएम ममता बनर्जी

मिथुन चक्रवर्ती बोले-उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा विवाद के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा- ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर हैं। उनका क्या दोष है। साथ ही उन्होंने कहा- राज्य में भाजपा नहीं, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। दरअसल, बुधवार को ममता बनर्जी ने इमामों की सभा में कहा था- मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लांड था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। साथ ही कहा- यूपी के सीएम योगी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वह सबसे बड़े भोगी हैं।

जब तक नई नियुक्तियां नहीं, अपने पद पर बने रहेंगे शिक्षक

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जब तक नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, शिक्षक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की राहत उन्हीं शिक्षकों को मिलने वाली है जिनकी नियुक्ति में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई थी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 26 हजार के करीब शिक्षकों का भविष्य अंधकार में आ गया था। जिन शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली पाई गई, उनकी नौकरी तो गई ही, इसके साथ-साथ उस समय सही तरीके से भी जिनकी नियुक्तियां हुई थीं, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा।

● बंगाल एसएससी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दी बड़ी राहत

लेकिन अब उन निर्दोष शिक्षकों को ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए राहत दे दी है। नई नियुक्ति शुरू होने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी में आती है, उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22 °c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 18 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पटना में महागठबंधन की बैठक, सीएम फेस-सीट शेयरिंग पर चर्चा

● मीटिंग से पहले पप्पू यादव की डिमांड- सीमांचल में कांग्रेस को अधिक सीट मिले

पटना (एजेंसी)। पटना में गुरुवार को महागठबंधन की बैठक संपन्न हो गई है। मीटिंग में आरजेडी से तेजस्वी यादव, संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंदन मोहन झा, वीआईपी से पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी, देव ज्योति, अन्य पार्टी से केडी यादव, अजय कुमार व राज्य सचिव कुणाल मौजूद रहे। इस दौरान चुनावी रणनीतियों, सीट बंटवारा, सीएम फेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2 दिन पहले दिल्ली में भी राजद-कांग्रेस की बैठक हुई थी। बैठक में जाने से पहले मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए वाले कमजोर हैं, इसलिए चाहते हैं हम आ जाएं। वीआईपी प्रमुख से एनडीए में जाने की चर्चा को लेकर सवाल किया गया था। वहीं बैठक से पहले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। बिहार की चौदह करोड़ जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। इसमें किसी को कोई भ्रम या संदेह नहीं है। सी वोटर सर्वे में भी तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हैं। 40 फीसदी से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को स्वीकार किया है। बैठक से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मांग की है कि सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में

कांग्रेस को अधिक सीटें मिलनी चाहिए। सीमांचल और कोसी कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से कि इन इलाकों में बिना जाति- धर्म की राजनीति है। इसलिए कांग्रेस को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम एनडीए को यहां हरा सकें। यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। मीटिंग में ये निर्णय जरूर हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में ज्यादा हो वहां से वहीं लड़े। सीमांचल-कोसी में कांग्रेस का अधिकार बनता है। बैठक से एक दिन पहले बुधवार को नालंदा में एक जनसभा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, जब तक हमारे पास 2-3 दर्जन विधायक नहीं होंगे, तब तक हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर हमारे पास इतने विधायक होंगे, तब जाकर हमारी सरकार बनेगी और मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वो डिप्टी बनेंगे। इस सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि किसे बनाया जाएगा।

पत्नी ने हत्या की, फिर 10 बार सांप से डसवाया

● बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर, दोनों गिरफ्तार

मेरठ (एजेंसी)। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात फिर हुई है। यहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10

बार डसा। वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घरवाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजन को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। बुधवार देर शाम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है।

चीन से बोरिया-बिस्तर समेट रहीं अमेरिका की कंपनियां

● फायदा उठाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर लगातार गहराता जा रहा है।

अमेरिका ने चीनी माल पर 245 फीसदी टैक्स लगा दिया है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में सामान बनाना फायदे का सौदा नहीं रह गया है और वे चीन में अपना बोरिया बिस्तार समेटने की तैयारी में हैं। भारत सरकार इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। सरकार चाहती है कि ये कंपनियां भारत में आकर अपना कारोबार करें। इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और दवाइयों जैसे सेक्टरों में फायदा होगा।

भारत ने सुरक्षा परिषद में दिया सुधार का प्रस्ताव

● इस्लामिक देशों के आरक्षण के प्रस्ताव को यूएन में ठुकराया

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। जी-4 देश, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी हैं, उसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं।

इसके तहत जी-4 देशों ने यूएनएससी में इस्लामिक देशों के लिए आरक्षण की मांग का विरोध किया, जिससे प्रस्ताव खारिज हो गया। वहीं भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 11 स्थायी सदस्यों के साथ कुल 25 या 26 सदस्यों तक विस्तार करने का सुझाव दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने यूएनएससी सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता में बोलते हुए कई सुझाव पेश किए हैं। नए संरचना की समीक्षा की मांग करती है।

राजनीतिक रूप से बदला ले रहे यह एजेंसियों का है दुरुपयोग

गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में बोले वाड्रा, तीसरे दिन भी पूछताछ

चंडीगढ़ (एजेंसी)। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। वह सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। एजेंसी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसे लेकर गुरुवार को वाड्रा ने कहा- यह राजनीतिक प्रतिशोध है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह गलत है। एजेंसियां देश में पद के किसी उम्मीदवार के पीछे पड़ जाती हैं या जब कोई पार्टी अच्छा काम कर रही होती है, तो उसे पकड़ लेती हैं।

एजेंसियों पर भरोसा कैसे होगा। ईडी ने भाजपा के किस मंत्री या सदस्य को समन भेजा है। क्या भाजपा में सभी अच्छे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। वाड्रा बोले कि भाजपा नेताओं पर भी कई आरोप हैं। उन्होंने कहा- मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अगर मुझ पर दबाव डालेंगे या परेशान करेंगे तो मैं और मजबूत होकर उभरूंगा। मेरे साथ लोगों की ताकत है, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जब यह पार्टी लोगों के साथ अन्याय करती है तो मैं उनके लिए बोलता हूं। मैं अन्याय के खिलाफ हूं।

एएपी नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा

विदेशी फंडिंग मामले में जांच एजेंसी का बड़ा ऐक्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (एएपी) के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। सीबीआई ने बुधवार को एएपी के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया। सीबीआई की

● सिसोदिया बोले-यह साजिश, गुजरात प्रभारी बनते ही रेड

एफआईआर के मुताबिक- विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को कुल 1.02 करोड़ का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। एएपी ने जवाब में कहा- 201 विदेशी नागरिकों ने पार्टी को डोनेशन दिया। 51 ईमेल आईडी के जरिए 639 बार में 2.65 करोड़ का दान किया। सभी डोनेशन पारदर्शी तरीके से हुए हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। एएपी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा- गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड हुई है। ये कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि

भाजपा की साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ एएपी ही उन्हें चुनौती दे सकती है। दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एएपी के संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल में सौरभ भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के तहत दुर्गेश पाठक गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी बढ़ती पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। फरवरी में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने 32 सीटें जीती थी और लगभग 250 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। वर्तमान में गुजरात विधानसभा में एएपी के चार विधायक हैं।

केन्द्रीय मंत्री शाह के निर्देशों के परिपालन में उच्च स्तरीय बैठक

मंत्री सारंग ने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा करें निर्धारित

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में दिये गये निर्देशों के परिपालन में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में गुरूवार को उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा निर्धारित कर कार्य-योजना बनाई जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे।

सहकारिता एक्ट और गाइडलाइन के अध्ययन के लिये कमेटी- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कमेटी गठित कर सहकारिता एक्ट और गाइडलाइन का अध्ययन किया जाये। यह कमेटी अपनी अनुशंसा उच्च स्तर पर प्रस्तुत करेगी। बैठक में कमेटी के सदस्यों में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त श्री के.के. द्विवेदी और श्री एच.एस.बघेला को शामिल किया गया है।

देशभर के सहकारिता अधिकारी समझेंगे सीपीपीपी- मंत्री श्री सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पाटनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर एक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश भी दिये। वर्कशॉप में देशभर के सहकारिता से जुड़ें अधिकारियों को सीपीपीपी मॉडल का प्रजेटेंशन दिया जायेगा। आगामी 20 जून को यह प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

मंत्री श्री सारंग ने सीपीपीपी मॉडल के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। सीपीपीपी मॉडल के तहत प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि रोजगार के नये अवसर सृजित करेगा।

पैक्स का विस्तार- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में अभी 10 हजार प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां है। सभी जिला अधिकारियों को इसको विस्तार करते हुए 26 हजार का लक्ष्य देकर तत्परतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये जाये। पैक्स का विस्तार टाइम लिमिट में करें। उन्होंने कहा कि 637 नई समितियों के गठन की कार्ययोजना बनाकर अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा कि जहां-जहां नई सोसायटियाँ गठित की जाना है वहां लक्ष्य तय कर त्वरित गति से कार्य किया जाये। उन्होंने नवाचार के संबंध में जेआर और डीआर की वीडियो कॉन्फेसिंग कर आवश्यक मार्गदर्शन दिये जाने के भी निर्देश दिये। बैठक में समितियों के चुनाव संबंध में भी चर्चा की गई।

निवेश विंग की स्थापना

बैठक में बताया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उच्च स्तर से निर्णय के बाद सहकारिता क्षेत्र में निवेशकर्ताओं को सभी आवश्यक सुविधाएँ एक स्थान पर सुनिश्चित करने के लिये निवेश विंग आई डब्ल्यू बनायी गई है। इसमें श्री अम्बरीष वैद्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता और प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेन्द्र दीक्षित समन्वय अधिकारी होंगे। निवेश विंग में मुख्य संयोजक सुश्री गुंजन राय और सहायक समन्वयक श्रीमती प्रियंका शाक्य रहेगी। बैठक में प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेन्द्र दीक्षित और संयुक्त आयुक्त श्री अम्बरीष वैद्य उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी

कहा-अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने

8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर व राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की 'सीमा' तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, 'राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया। धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की इन-हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

संकट मोचन संगीत समारोह

बांसुरी सम्राट की जिद के आगे नतमस्तक हुए महंतजी...

राजेन्द्र शर्मा
(कला समीक्षक एवं उप्र सरकार में अधिकारी)

संकट मोचन संगीत समारोह के पहले दिन पहली प्रस्तुति ही ऐसा मील का पत्थर साबित हुई ,जिसमें 86 वर्षीय बॉसुरी सम्राट हरि प्रसाद चौरसिया ने जिद पकड़ ली कि उनके साथ बतौर संगीतकार महंत विशम्भर नाथ मिश्र ही होगें। पंडितजी के हठ के आगे संकट मोचन मंदिर के महंत और संकट मोचन संगीत समारोह के संयोजक महंत विशम्भर नाथ मिश्र को नतमस्तक होना ही पड़ा । लगभग पौन घंटे की जुगलबंदी के बाद महंत विशम्भर नाथ मिश्र ने कह उठे कि पंडित जी के साथ जुगलबंदी करते हुए मेरी तो हवा ही निकल गई और पं. हरि प्रसाद चौरसिया ने मंच से कहा कि महंतजी के साथ जुगलबंदी करते हुए मैं नर्वस हो रहा था। इस प्रस्तुति में जो घटा, उसे समझने के लिए 59 साल पहले का किस्सा जानना जरुरी है।

इस किस्से की शुरुआत साल 1976 से हुई। संकट मोचन संगीत समारोह के संस्थापक पंडित अमर नाथ मिश्र अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच जब फुरसत में अपने प्रिय वाद्य पखावज पर हाथ आजमाते। उस समय दस बरस के उनके पौत्र विशम्भर नाथ मिश्र कौतुहल से अपने बाबा को निहारते रहते । एक दिन बाबा अमर नाथ मिश्र ने बालक विशम्भर को अपने अपने पास बैठाकर पखावज वादन सिखाना शुरू किया।

संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन 1923 से होता आ रहा है लेकिन पंडित अमर नाथ मिश्र ने 1977 तक कभी पखावज वादन की अपनी प्रस्तुाति समारोह में नहीं दी। पचपनवें समारोह में महंतजी ने जब पखावज वादन की अपनी प्रस्तुति दी तो संगीत रसिक उनका सधा वादन देखकर हैरत में पड़ गए। लेकिन बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, दाम्पत्य जीवन, आईआईटी बीएचयू में अध्यापन, पहलवानी, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के चलते प्रो. विशम्भर नाथ मिश्र को पखावज रियाज करने का समय ही नहीं मिला ।

साल 2013 में संकट मोचन मंदिर के महंत का गुरुत्तर दायित्व मिलने के बाद पखावज वादन की उनकी अकुलाहट बढ़ती गई। मिश्र ने तय किया कि वो पखावज वादन की अपने बाबा की परंपरा को हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। लीक से हटकर काम करने का संस्कार उन्होंनें अपने पूर्व महंत वीरभद्र मिश्र से वंशानुगत पाया है।

साल 2019 में दिल्ली में 'सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित 15वें सामापा संगीत सम्मेलन में दुर्लभ वाद्य पखावज वादन की एकल प्रस्तुत कर महंत विशम्भर नाथ मिश्र ने संगीत प्रेमियों को चकित कर दिया। वाराणसी में हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने ध्रुपद मेले में महंतजी यदा कदा पखावज वादन बतौर संगतकार करते रहे। बाद में उनके मित्र गुंदेचा बंधु के आग्रह पर उन्होंने बतौर संगतकार पखावज वादन कर साल 1978 का इतिहास दोहरा दिया ।

दशकों से संकट मोचन संगीत समारोह में हाजिरी लगा रहे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को यह इल्मंही नहीं था कि महंत विशम्भर नाथ मिश्र बेहतरीन पखावज वादक भी हैं। हाल ही में 29 मार्च को बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय के कौस्तुभ जयंती समारोह में पद्मश्री ऋत्विक सान्याल का कार्यक्रम हुआ तो ऋत्विक ने बतौर संगतकार महंत विशम्भर नाथ मिश्र से पखावज वादन का अनुरोध किया गया। उनकी यह प्रस्तुति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसी समय पंडित जी ने ठान लिया था कि इस बार संकट मोचन संगीत समारोह में उनके संगतकार महंत विशम्भमर नाथ मिश्र ही होगें।

इस संगीत समारोह के 101 वे आयोजन की पांचवीं निशा में सर्व प्रथम पं. हरिप्रसाद चौरसिया की प्रस्तुति रखी गई। विचार यह था कि पं. हरि प्रसाद चौरसिया प्रस्तुाति देकर मंदिर के अतिथिगृह में विश्राम कर सकेंगे। प्रस्तुति से लगभग आधे घंटे पहले चौरसिया जी ग्रीन रुम पहुंचे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं और मेरे मित्र डॉ. प्रकाश चंद गिरि चौरसिया जी के चरण स्पर्श करने जैसे तैसे ग्रीन रुम में पहुंचे तो चौरसियाजी ने हाथ हिलाकर ही हमे आशीर्वाद दिया। एक शब्द भी उनसे बोला नहीं जा रहा था ।

इसी ऊहा पोह में चौरसिया जी ने मंच पर ने चलने के लिए हाथ से इशारा किया। वो व्हील चेयर पर मंच तक आए। मंच पर लगी कुर्सी पर बैठकर जैसे ही पंडितजी ने कांपते हाथों से बांसुरी में तान फूंकी तो मानो चमत्कार हो गया। बांसुरी का वही चिरपरिचित माधुर्य, तान और सुरों का भावपूर्ण संधान। विराम प्रस्तुाति में पंडितजी ने जब बांसुरी पर 'ओम जय जगदीश हरे' -- की धुन बजाई तो पूरा प्रांगण 'हर हर महादेव' से गूंज उठा। पंडितजी ने अस्वस्थता के कारण अपने स्थान पर प्रस्तुति हेतु अपने भतीजे पंडित राकेश चौरसिया का नाम दिया। लेकिन असमंजस की हालत में वह संकट मोचन को अर्ज लगाते रहे मेरे प्रभु क्याट मुझसे अंजाने में ही कोई गलती हो गयी।

जब चौरसिया जी को यह विश्वासस हो गया कि संकट मोचन ने हाजिरी लगाने से मनाही नहीं की है तब उन्होंने तुरत फुरत संकट मोचन के महंत प्रो. विशम्भर नाथ मिश्र को फोन पर पूछा कि महंत जी, हमे भूल गये हैं क्या ? महंत जी ने उत्तर दिया कि हमको लगा था कि आपकी व्यस्तता है। मैं किसी को बुलाने वाला कौन होता हूं। हनुमान जी ही यहां सबको बुलाते है। उनकी ही प्रेरणा से आपने हमको फोन किया है। इसके बाद पंडितजी ने सूचित किया कि वह गत वर्ष के आयोजन की दूसरी निशा को संकट मोचन के दरबार में हाजिरी देने आ रहे हैं। उन्होंने हाजिरी दी और श्रोताओं को अपने बेमिसाल वादन से मंत्रमुग्ध किया। संकट मोचन का आंगन पहली प्रस्तुति में मधुवन बना जब हरि (पंडित हरि प्रसाद चौरसिया) की बांसुरी कान्हा बनकर महंत विशम्भर नाथ मिश्र की पखावज रुपी राधा को रिझाने लगी। संकट मोचन के दरबार में सबसे पहले बांसुरी पर राग विहान गूंजा तो परिसर भर में फैले भक्तों, श्रोताओं का जमघट आंगन में लग गया। प्रस्तुति के दौरान पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने तीन बार बांसुरी बदली, उनके होठों के कंपन भी सुर बन जा रहे थे। प्रस्तुति का समापन ओम जय जगदीश हरे... की धुन से किया। इन पंक्तियों के लेखक से पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने कहा कि - जब तक सृष्टि रहेगी तब, मैं हाजिरी लगाने आता रहूंगा। अब हर बार संगतकार के रुप में पखावज महंतजी ही बजाएंगे।

निजी अस्पताल में महिला कर्मचारी से मारपीट

सहकर्मी ने मंदिर यात्रा को लेकर की निजी टिप्पणी, केस दर्ज

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में विजयनगर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर अभद्र टिप्पणी करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजयनगर थाना पुलिस के अनुसार, 36 वर्षीय महिला अस्पताल के आईसीयू विभाग में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करती है। पीड़िता ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत मुकेश नामक कर्मचारी से उसकी मित्रता है। कुछ दिन पहले वह मुकेश और उसके परिवार के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए गई थीं। यात्रा से लौटने के बाद अस्पताल में कार्यरत अर्जुन चोपड़ा ने दोनों को लेकर आपत्तिजनक और निजी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि अर्जुन ने मुकेश के मोबाइल पर भी व्यक्तिगत और अनुचित कमेंट्स किए। इसी बात को लेकर 15 अप्रैल की रात मुकेश और अर्जुन के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना की जानकारी मिलने पर जब महिला ने अर्जुन से इस विषय में बात करने की कोशिश की, तो आरोपी ने अस्पताल परिसर में ही महिला से अभद्र भाषा में बात की और मारपीट की।झ महिला का कहना है कि घटना के दौरान अन्य स्टाफ भी मौके पर मौजूद था। इसके बाद वरिष्ठ स्टाफ को सूचना दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।

भस्म आरती दर्शन

त्रिनेत्र धारण कर बाबा महाकाल का राजा स्वरूप श्रृंगार

उज्जैन (एजेंसी)। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार तड़के भस्म आरती के दौरान चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक और दूध,दही, घी,शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। भगवान महाकाल को मस्तक पर रजत, चंद्र, भांग, चन्दन और गुलाब के फूल की माला अर्पित की। त्रिनेत्र त्रिपुण्ड अर्पित कर बाबा महाकाल का राजा स्वरूप श्रृंगार करने के पश्चात कपूर आरती के बाद जटाधारी बाबा महाकाल को रजत मुकुट, त्रिपुण्ड अर्पित किया गया।झ श्रृंगार पूरा होने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढांककर भस्मी रमाई गई। भगवान महाकाल का भांग ड्रायफ्रूट और आभूषण के साथ फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भस्म अर्पित करने के पश्चात शेषनाग का रजत मुकुट रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगन्धित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की। गुलाब के सुगंधित पुष्प धारण किये भगवान महाकाल ने। फल और मिष्ठान का भोग लगाया भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महानिर्वाणी अखाड़े की और से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गयी। मान्यता है की भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते है।

इंदौर में महिला पटवारी से छेड़छाड़, आरोपी हिरासत में

ऑफिस आने-जाने के दौरान करता था पीछा, कहता-उसके जैसी महिला घर में रहने लायक

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर की एक महिला पटवारी ने इलाके में रहने वाले युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। महिला पटवारी के मुताबिक आरोपी उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। तंग आकर बुधवार को महिला पटवारी थाने पहुंची और छेड़छाड़ की धाराओं एफआईआर करवा दी। मल्हारगंज पुलिस ने इलाके में रहने वाली एक महिला पटवारी की शिकायत पर गौरव चौहान पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि गौरव चौहान जनवरी माह से उनका पीछा कर रहा है। आरोपी पीछा करते हुए कई बार उनके ऑफिस तक आ गया। रास्ते में आने जाने के दौरान भी कमेंट्स करता रहता है। घर की खिड़की से भी बुरी नीयत से देखता है। सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बैठा रहता है। कुछ दिन पहले गौरव ने रास्ते में रोका और कहा कि वह अच्छी लगती है। उसके जैसी महिला घर में रहने लायक है। उसकी हरकतों से परेशान होने के बाद महिला पटवारी ने अपनी मां से बात की और आरोपी पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है।

बैंक को बम से उड़ाने की धमकी

मैनेजर को भेजा ईमेल, कहा- रिमोट कंट्रोल से करेंगे ब्लास्ट ; पुलिस फोर्स तैनात

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बैंक मैनेजर को धमकी भरा मेल मिला। इसमें दोपहर 2 बजे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट करने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला सियागंज क्षेत्र के पीएनबी ब्रांच का है। बैंक अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर अज्ञात ई-मेल मिलने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। कोतवाली थाना पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम वहां पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे तक बैंक परिसर की गहन तलाशी ली, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसीपी विनोद कुमार दीक्षित ने बताया बैंक के मैनेजर को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें दोपहर 2 बजे बैंक को रिमोट कंट्रोल से उड़ाने की बात की गई थी। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है।

इंदौर में कांग्रेस नेता सोनिया-राहुल गांधी का पुतला फूंका

नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, 'चोर मचाए शोर' के लगाए पोस्टर

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के राजवाड़ा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। युवा मोर्चा ने पुतला दहन से पहले राजवाड़ा पर उस पुतले की परिक्रमा करवाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी चोर है के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं, पुतले पर चोर मचाए शोर और नेशनल हेराल्ड से जुड़े पोस्टर भी चिपकाए गए।

भाजयुमो अध्यक्ष बोले- कांग्रेस सरकार में ही केस दर्ज हुए

इंदौर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने कहा कि ईडी देश की एक सर्वोच्च संस्था है, जो बड़े घोटालों को उजागर कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर घोटाले के आरोप उनकी ही सरकार के समय दर्ज किए गए थे। अब जब ईडी सही दिशा में जांच कर रही है, तब ये दोनों ईडी कार्यालय जाकर अधिकारियों को धमकाने और जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश को लूटने का काम किया है। आज इंदौर में युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। आलाकमान के निर्देश पर प्रदेशभर में अलग-अलग स्थानों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। पुतलों पर चोर मचाए शोर और नेशनल हेराल्ड से जुड़े पोस्टर भी चिपकाए गए।

कांग्रेस ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

इधर, कांग्रेस ने गुरुवार को फिर इंदौर में ईडी कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आज ईडी कार्यालय के बाहर पिंजरे में प्रतीकात्मक तोते लटकाएं। प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मोदी सरकार के कहने पर जिस तरह ईडी द्वारा दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्ज शीट पेश की गई है, वो निश्चित ही यह दर्शाती है कि ईडी मोदी सरकार का तोता हो गई है। जिस तरह तोते को सिखाया जाता है, वैसे ही तोता बोलता है। ठीक इसी प्रकार ईडी मोदी सरकार के कहने पर कार्यवाही कर रही है।

9 महीने का बच्चा घर से किडनैप

भाई तुतलाते हुए बोला-मां, कोई भय्यू को ले गई ; सीसीटीवी फुटेज से महिला की पहचान, गिरफ्तार

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में 9 माह के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा जब घर में नहीं दिखा तो परिजन ने तलाश शुरू की। बच्चे के पिता संतोष सेन ने फौरन पुलिस को बच्चे के गुम होने की सूचना दी। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर में गुरुवार सुबह की है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो एक अज्ञात महिला 9 माह के नकुल को उठाकर ले जाती हुए नजर आई। घटना के समय बच्चा कमरे में था। मां घर के काम में लगी थी और बड़ा भाई मोबाइल चला रहा था।

महिला चुपचाप बच्चे को लेकर निकल गई- ताक लगाए आरोपी महिला ने घर में झांका। उसे केवल बच्चे दिखाई दिए। मौका पाकर वह चुपचाप बच्चे को लेकर निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे के बड़े भाई ने मां से कहा- मां...भय्यू को ले गई। ये सुनकर मां बाहर आई तो बच्चा गायब था।

बच्चे को बरामद किया, महिला गिरफ्तार- घबराए परिजन ने फौरन पुलिस को सूचना दी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, चार टीमें गठित की गई थी। महिला बच्चे को लेकर पीसी सेठी अस्पताल तक पहुंच गई थी। यहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर बबीता उर्फ भूरी चौरसिया नाम की महिला को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद आसपास के लोगों ने महिला को पहचान लिया। आरोपी बबीता भी गौरी नगर की रहने वाली है।

एआईसीटीएसएल बोर्ड बैठक : प्रमुख मार्गों पर चलाएंगे एसी बसें

जहां जरुरत वहां अतिरिक्त बसें भी चलाएंगे, बीआरटीएस की विज्ञापन पॉलिसी भी अलग से बनेगी

इंदौर (एजेंसी)। गुरुवार को अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के प्रमुख मार्गों पर एसी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ रास्तों को चिह्नित किया जाएगा। बीआरटीएस हटाए जाने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए। आई बस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों व ऑटोमैटिक डोर के संचालन व रखरखाव संबंधी एजेंसी, 30 सीएनजी बसों के संचालन संबंधी एजेंसी, ट्रैफिक सिग्नल मेंटेनेंस हेतु कार्यरत एजेंसी, कॉरिडोर, आई बस स्टेशन, रेलिंग, यूनीपोल, स्ट्रीट लाइट पोल पर कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन के लिए एजेंसियों को नियमानुसार कामकाज सौंपा जाएगा। बैठक में एआईसीटीएसएल बोर्ड के चेयरमेन व महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उपाध्यक्ष एवं संभागायुक्त दीपक सिंह, डायरेक्टर और कलेक्टर आशीष सिंह, एमडी व निगमायुक्त शिवम वर्मा, डायरेक्टर और आईडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, सीईओ दिव्यांक सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सीमेंट कारोबारी की मौत पर परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा

जिला कोर्ट ने दिए इंश्योरेंस कंपनी को आदेश,आयकर रिटर्न भरना बना मजबूत आधार

इंदौर (एजेंसी)। तीन साल पहले एक सीमेंट कारोबारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में जिला कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवार को 97 लाख रुपए दे। यह राशि ब्याज सहित कुल 1.11 करोड़ रुपए बनती है, जिसे एक माह के भीतर अदा करना होगा। इस केस में कारोबारी द्वारा बीते चार सालों में नियमित रूप से भरा गया इनकम टैक्स रिटर्न, मुआवजे के लिए एक मजबूत आधार बना। सीमेंट कारोबारी का नाम पंकज चावला (36), निवासी हिम्मतनगर था। दुर्घटना 1 अगस्त 2022 को इंदौर-उज्जैन रोड पर नरवर के पास हुई थी। चावला अपने दोस्त धर्मेंद्र और कन्हैया के साथ स्कूटी से उज्जैन जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 22 अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में पत्नी, चार बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं, जो पूरी तरह से उन पर आश्रित थे। हादसे के बाद, परिवार ने 15 अक्टूबर 2022 को जिला न्यायालय में पांच करोड़ रुपए की क्लेम राशि के लिए याचिका दायर की। इसमें ट्रक चालक, ट्रक मालिक और 'दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी' से मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। यह केस करीब तीन साल तक चला।

आयकर रिटर्न भरना बना मजबूत आधार- एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने इस केस में परिवार की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए अलग-अलग मदों में कुल 97.36 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि ब्याज सहित कुल 1.11 करोड़ रुपए बनती है, जिसे एक महीने के भीतर अदा करना होगा। केस के दौरान पंकज चावला की आय का सबसे मजबूत प्रमाण उनके द्वारा पिछले चार सालों में भरा गया आयकर रिटर्न रहा। कारोबारी की उम्र 36 साल थी, जिसे देखते हुए उनकी भविष्य की संभावित आय और छह आश्रितों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया गया।

इसलिए जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न भरना- एडवोकेट खंडेलवाल के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति जो आत्मनिर्भर हैं और आयकर के दायरे में आते हैं, खासकर छोटे कारोबारी, उन्हें नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद जरूरी है। यह दस्तावेज आय का सबसे ठोस प्रमाण होता है।

कार सवार और कांग्रेस नेता के पोते के बीच विवाद

एक ने छुरा दिखाया, दूसरे ने जंजीर से मारपीट की ; दोनों पक्षों पर केस दर्ज

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता के पोते और एक कार सवार युवक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम पुलिस के अनुसार, आर्यमन शुक्ला, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपा शंकर शुक्ला का पोता है, महावीर कृपा एवेन्यू, शुक्ला नगर में रहता है। आर्यमन ने शिकायत में बताया कि वह रविवार को अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक कार वहां से गुजरी और उसका पहिया उसके पैर पर चढ़ गया। जब उसने कार सवार को रोककर बाहर आने के लिए कहा, तो युवक ने अपशब्द कहे और कार से उतरकर छुरा निकाल लिया। आर्यमन का आरोप है कि आरोपी ने उस पर हमला करने की कोशिश की और मारपीट की। बीच-बचाव में उसका एक दोस्त भी घायल हुआ। जब दोस्तों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, तो आरोपी ने उनके मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिए। इसके बाद आरोपी ने पास पड़ी ईंट भी उठा ली और धमकाते हुए अपशब्द कहता रहा। दूसरी ओर, बीटेक के छात्र अमित माईती ने आर्यमन शुक्ला और उसके दोस्तों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अमित के अनुसार, वह अपने दोस्त हार्दिक के साथ कार से गौतम आश्रम जा रहा था। रास्ते में कांग्रेस नेत्री सोनिया शुक्ला के घर के बाहर एक कार खड़ी थी, जिससे रास्ता बाधित हो रहा था। जब उसने कार में बैठे युवक को इशारा कर कार हटाने को कहा, तो आर्यमन नीचे उतरा और अपशब्द कहने लगा। अमित का आरोप है कि आर्यमन ने जंजीर निकाली और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने मिलकर उस पर हमला किया। घटना में अमित के चेहरे, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।

इंदौर से 100 किमी दूर जाकर किया तेंदुए का रेस्क्यू

खरगोन के जंगल में शिकारियों के फंदे में फंसा रहा तेंदुआ, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा

इंदौर (एजेंसी)। तेंदुओं के शिकार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। धामनोद-बाग रेंज के बाद अब खरगोन वनमंडल की कसरावद रेंज में तेंदुए के शिकार की एक और घटना सामने आई है। शिकारियों ने जंगल में तीन स्थानों पर वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिए फंदे लगाए थे। इन्हीं में से एक फंदे में मंगलवार रात एक तेंदुआ फंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही इंदौर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा। उसे ट्रैंकुलाइज कर बेहोश करने के बाद पशु चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। तेंदुए को केवल मामूली चोटें आई थीं, इसलिए चिकित्सकों ने उसे फिर से जंगल में छोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने बुधवार को तेंदुए को इंदौर से लगे जंगलों में छोड़ दिया।

घटना खरगोन रेंज के तहत आने वाले मथलाई गांव के खेत की है, जहां एक मादा तेंदुआ घायल अवस्था में दिखाई दी। वह काफी देर तक एक ही स्थान पर बैठी रही। यह देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। कसरावद रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। वनकर्मियों ने तेंदुए की निगरानी की और ग्रामीणों को उससे दूर रखा। मंगलवार देर रात रालामंडल अभयारण्य की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। इंदौर सीसीएफ पी.एन. मिश्रा और डीएफओ प्रदीप मिश्रा से अनुमति मिलने के बाद बुधवार सुबह पांच बजे टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचते ही ट्रैप फंदा दिखाई दिया, जिसमें तेंदुआ फंसा हुआ था। सर्चिंग के दौरान पाया गया कि खेत में तीन अलग-अलग स्थानों पर फंदे लगाए गए थे। रेस्क्यू टीम के सदस्य शेरसिंह कटार ने ट्रैंकुलाइज गन से तेंदुए को निशाना बनाया। लगभग 15 मिनट में तेंदुआ बेहोश हो गया। पशु चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की।

नेहरू पार्क का स्विमिंग पूल सुधरेगा, राष्ट्रीय स्पर्धाएं हो सकेंगी

4 करोड़ से संवारेंगे, पूल के अंदर वाटरप्रूफ टाइल्स लगाई जा रही, आधुनिक लाइट की व्यवस्था भी की जा रही

इंदौर (एजेंसी)। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार इसी माह पूरा होगा। इस पुल का निर्माण कई साल पहले हुआ था। तब से अब तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। अब इसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल की एक कंपनी यह कार्य कर रही है।झ पार्षद और सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ यहां निरीक्षण किया। निगम द्वारा संचालित इस पुल की हालत काफी खराब हो चुकी थी। चैंजिंग रूम में पानी टपकता था। ऊंचाई वाले ट्रैक की स्थिति भी जर्जर थी। कुछ महीने पहले भूमिपूजन कर जीर्णोद्धार की शुरुआत की गई थी। कंपनी को अप्रैल अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पूल के अंदर वाटरप्रूफ टाइल्स लगाई जा रही है। आधुनिक लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है। दो फिल्टर प्लेट की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी। पुराने और नए दोनों सिस्टम का समावेश होगा। खिलाड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान टाइल्स लगाने में लापरवाही दिखी। इस पर पहाड़िया ने ठेकेदार को फटकार लगाई।

प्रीतमलाल दुआ सभागृह का रिनोवेशन 30 जून तक पूरा होगा

शहर के बीच स्थित प्रीतमलाल दुआ सभागृह के रिनोवेशन का काम 30 जून तक पूरा होगा। बुधवार को संभागायुक्त दीपक सिंह ने आईडीए अधिकारियों के साथ सभागृह का निरीक्षण किया।

सिंह ने सभागृह के मुख्य ऑडिटोरियम सहित पेंटिंग प्रदर्शनी कक्ष और हॉल को देखा। इस मौके पर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुआ सभागृह में फर्श, लाइटिंग, कुर्सियां लगाना, वातानुकूलित व अन्य निर्माण 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र है

सिंह ने आईडीए के अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। पेंटिंग प्रदर्शनी कक्ष और मुख्य हॉल का रिनोवेशन बारिश से पहले हो जाए। कलाकारों व आम नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विशेष ध्यान रखा जाए।

संपादकीय

उर्दू पर नफीस फैसला !

सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू भाषा को लेकर एक नफीस और दो टूक फैसला यह कहकर दिया है कि उर्दू भारत की ही भाषा है तथा भाषा का कोई धर्म नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा को मज़हब से जोड़ना गलत है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना असलियत और विविधता में एकता से दूर जाने जैसा है। याचिकाकर्ता वर्षाताई बागड़े ने नगर परिषद के साइन बोर्ड या नेमप्लेट पर मराठी के साथ उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि नगर परिषद का काम केवल मराठी में ही होना चाहिए और उर्दू का उपयोग, यहां तक कि नेमप्लेट पर भी सही नहीं है। इससे पहले, नगर परिषद और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भाषा कोई मज़हब नहीं होती और न ही यह किसी मज़हब का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा एक समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति है और सभ्यता की प्रगति को मापने का पैमाना है। उर्दू उत्तरी और मध्य भारत की मिली-जुली सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। कोर्ट ने उर्दू के प्रति भेदभाव को खारिज करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। उर्दू एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो भारत में ही जन्मी और यहीं पर फली-फूली. कोर्ट ने बताया कि सदियों से उर्दू ने कई प्रसिद्ध कवियों की पसंदीदा भाषा बनकर अपनी शुद्धता हासिल की। कोर्ट ने यह भी कहा कि रोज़मर्रा की हिंदी में बिना उर्दू शब्दों के बातचीत संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण तब रुक गया, जब दोनों पक्षों ने हिंदी को संस्कृतनिष्ठ और उर्दू को फारसी की ओर ले जाना शुरू किया। कोर्ट ने 2022 के महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (आधिकारिक भाषा) अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि इसमें उर्दू के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि उर्दू की वाक्य रचना और कुछ हद तक व्याकरण भी हिंदी जैसा है। दोनों आपस में इतनी घुली मिली हैं कि दोनों भाषाओं से एक दूसरे के शब्दों को अलग करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। फर्क है तो केवल लिपि का। भाषा विज्ञान के अनुसार उर्दू भी उसी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की सदस्य है, जिसकी हिंदी है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ राजनीतिक दल और संगठन उर्दू को विदेशी भाषा के रूप में पेश करके इसका विरोध करते रहे हैं। यह कहकर कि इसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर थोपा। विदेशी आंक्राता मुसलमानों की भाषा कभी उर्दू थी ही नहीं। वह या तो तुर्की थी, फारसी थी या फिर दारी थी। अरबी आदमी उर्दू नहीं समझ सकता और न ही उसे पढ़ सकता है। दरअसल भाषा के शुद्धतावादियों से दोनों ही भाषाओं को समान रूप से खतरा है। उर्दू की नफासत से हिंदी समृद्ध होती है और हिंदी की प्रांजलता उर्दू में लोकप्रियता और सहजता का रंग भरती है। बिना हिंदी के उर्दू बेमजा है और बिना उर्दू के हिंदी बेरंग है। उर्दू को समृद्ध करने में मुसलमानों के साथ हिंदुओं, सिखों का भी योगदान है। यानी उर्दू सर्वसमावेशी है। भाषा की इसी आत्मा को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से संतृप्त किया है।

नजरिया

बलदेव राज भारतीय

लेखक स्तंभकार हैं।

आठवें वेतन आयोग के गठन में इतना विलंब क्यों?

वेतन आयोग भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद से नियमित रूप से चली आ रही है, जिसमें हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग, जिसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था, ने अपनी सिफारिशें नवंबर 2015 तक दे दी थी। जिससे सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से अपने समय पर लागू हो गया था। अब आठवां वेतन आयोग जिसको जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, के गठन की घोषणा हुए भी चार महीने बीतने को हुए, परन्तु अभी तक सरकार द्वारा घोषणा के अतिरिक्त अन्य कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। आठवां वेतन आयोग जिससे अपेक्षा की जा रही है कि वो न केवल वेतन संरचना में बदलाव लाएगा, बल्कि महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए एक नया ढांचा तैयार करेगा।

जनवरी 2025 में जब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, तो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह घोषणा उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी, क्योंकि वेतन आयोग का गठन न केवल उनकी आय को बढ़ाने का वादा करता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई के दबाव को कम करने का भी एक अवसर प्रदान करता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह उत्साह धीरे-धीरे निराशा और बेचैनी में बदलने लगा। अप्रैल 2025 भी आधा बीत गया, मगर अभी तक न तो वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है, न ही इसका कोई अध्यक्ष घोषित किया गया है, और न ही इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनता या विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। यह देरी न केवल कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरने में बाधा बन रही है, बल्कि यह सवाल भी उठा रही है कि क्या सरकार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर पाएगी।

वेतन आयोग भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद से नियमित रूप से चली आ रही है, जिसमें हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग, जिसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था, ने अपनी सिफारिशें नवंबर 2015 तक दे दी थी। जिससे सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से अपने समय पर लागू हो गया था। अब आठवां वेतन आयोग जिसको जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, के गठन की घोषणा हुए भी चार महीने बीतने को हुए, परन्तु अभी तक सरकार द्वारा घोषणा के अतिरिक्त अन्य कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। आठवां वेतन आयोग जिससे अपेक्षा की जा रही है कि वो न केवल वेतन संरचना में बदलाव लाएगा, बल्कि महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए एक नया ढांचा तैयार करेगा।

आठवें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने इसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। बढ़ती महंगाई, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत ने कर्मचारियों के मासिक बजट पर भारी दबाव डाला है। विशेष रूप से मध्यम और निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह वेतन वृद्धि किसी वरदान से कम नहीं होगी। लेकिन इस प्रक्रिया में हो रही देरी उनकी उम्मीदों पर अनिश्चितता की काली घटाओं की तरह मंडरा रही है।

आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, सरकार को इस आयोग के लिए उपयुक्त अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करना होगा, जो न केवल अनुभवी हों, बल्कि विभिन्न हितधारकों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम हों। दूसरा, आर्थिक स्थिति भी इस देरी का एक कारण हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में कई चुनौतियों से गुजरी है, जिसमें वैश्विक मंदी, महामारी के प्रभाव और मुद्रास्फीति शामिल हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है, और संभवतः सरकार इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर रही है। तीसरा, वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। आयोग को न केवल वेतन संरचना की समीक्षा करनी होती है, बल्कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने, डेटा विश्लेषण करने और फिर अपनी सिफारिशें तैयार करने में भी महीनों लग सकते हैं। इसके बाद सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा करनी होती है, जिसमें कई बार संशोधन और कटौती भी शामिल होती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि यदि वेतन आयोग का काम समय पर शुरू न हो, तो जनवरी 2026 तक इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया है। कई संगठनों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के सदस्यों की घोषणा करे और इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से शुरू करे। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर देरी और बढ़ी, तो उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

आठवां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनकी खर्च करने की क्षमता बाजार को गति देती है। वेतन वृद्धि से न केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि इससे उपभोक्ता मांग में भी वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा, वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने में भी मदद करता है। यह आयोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की विशिष्ट जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, रक्षा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की अलग-अलग चुनौतियां होती हैं, और वेतन आयोग इन सभी पहलुओं पर विचार करता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए भी यह आयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय को भी महंगाई के अनुरूप समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

यदि आठवें वेतन आयोग के गठन में और देरी होती है, तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले, कर्मचारियों का सरकार के प्रति विश्वास कम हो सकता है। दूसरा, यह देरी कर्मचारियों की वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कई कर्मचारी इस वेतन वृद्धि के आधार पर अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तीसरा, अगर आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है, जिससे कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, देरी से सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। यह सरकार की छवि को प्रभावित करेगा। इससे कर्मचारियों का विश्वास प्रभावित होगा जिससे उनकी कार्य के प्रति अभिरुचि पर प्रभाव पड़ सकता है।

आठवें वेतन आयोग को समय पर लागू करने के लिए सरकार को तत्काल कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करना होगा। इसके लिए सरकार को अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्तियों का चयन करना चाहिए, जो इस जटिल प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकें। दूसरा, सरकार को कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद शुरू करना चाहिए, ताकि उनकी मांगों और सुझावों को प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही शामिल किया जा सके। तीसरा, सरकार को इस प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आयोग को अपनी सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत करनी हैं, तो इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आयोग को सभी आवश्यक संसाधन और डेटा समय पर उपलब्ध हों, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा सके।

आठवां वेतन आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में हो रही देरी ने कर्मचारियों की उम्मीदों पर अनिश्चितता का साया डाल दिया है। सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें समय पर प्रस्तुत कर सके और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। कर्मचारियों की यह उम्मीद अब सरकार की जिम्मेदारी है, और इसे पूरा करने के लिए समय कम बचा है।

मुद्दा

चेतनादित्य आलोक

वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

मुर्शिदाबाद हिंसा कांड पर कुछ अनुत्तरित सवाल

पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में वैसे तो वक्फ कानून का विरोध 08 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद इलाके में माहौल अचानक तब बिगड़ गया, जब लगभग 150 लोगों ने मोहल्ले के निहत्थे और मासूम निवासियों जोरदार हमला कर दिया। जब 51 साल की बेबस और लाचार महिला जानकी मंडल ने फूट-फूट कर रोते हुए अपनी आंखों के सामने घटी घटना का टीवी पर वर्णन किया तो सचमुच बहुत दुःख हुआ। वह बता रही थीं कि बेकाबू भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगा दी। पुरुषों को मारा-पीटा और सबकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी-बहुओं और माताओं का मान लूटने की कोशिश की। उग्र भीड़ में शामिल आतताइयों ने मोहल्ले वालों को धमकी दी कि भाग जाओ, वरना मारे जाओगे और लाचार मोहल्ले वाले चुपचाप यह सब देखते-सुनते रहे। फिलहाल, अपने ही देश में मालदा के वैष्णव नगर स्थित एक स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहीं जानकी मंडल ने यह भी बताया कि कैसे वह अपनी इज्जत और जान बचाकर बच्चों के साथ वहां से भागी थीं। बता दें कि यह पीड़ा केवल जानकी मंडल की नहीं, बल्कि वैष्णव नगर के स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग 04 दर्जन हिंदू परिवारों की भी है, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता होगी कि मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के सबसे अधिक पीड़ित और दुखी धुलियान कस्बे के लोग ही हैं।

और ऐसा सोचने की भूल तो कदापि नहीं करनी चाहिए कि इस भयावह पीड़ा और संत्रास वाली निमर्म घटनाओं की चौहद्दी धुलियान कस्बे तक ही सीमित है, बल्कि सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद के विभिन्न इलाकों से आने वाली इस पीड़ा और संत्रास की आर्त चीखें दूर-दूर तक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए हृदय विदारक रही हैं। जाहिर है कि दुःख-दर्द, निराशा, हताशा, बेबसी, लाचारी और आक्रोश से भरी बिल्कुल धुलियान के लोगों जैसी ही कहानियां कई अन्य इलाकों की भी है। टीवी चैनलों की भीड़ में एक चैनल पर शमशेरगंज इलाके के प्रसेनजीत दास ने भी रोते-कलपते हुए अपनी आपबीती तथा आंखों देखी घटनाएं टीवी पर बताई। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के मृतकों में से दो लोग प्रसेनजीत दास के परिवार से ही थे। मृतकों में एक उनका चचेरा भाई हरगोविंद दास और दूसरा भतीजा चंदन था। प्रसेनजीत ने जैसा टीवी पर बताया उसके अनुसार 10 अप्रैल की रात में लगभग 400 लोगों की भीड़ तलवार और छुरियां लहराते हुए मोहल्ले में घुसी। भीड़ में शामिल आतताइयों ने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों आदि में तोड़-फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। आंखों में भय भरकर प्रसेनजीत ने बताया कि भीड़ बहुत उग्र थी, इसलिए हमलोग उनसे भीड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जो कुछ वे करते रहे हमलोग चुपचाप देखते रहे।

उक्त घटना के संबंध में एक अन्य बेहद खौफजदां व्यक्ति ने बताया कि भीड़ की उग्रता और आतंक इतना था कि कोई कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इसलिए सभी अपनी-अपनी जान बचाकर भागने में ही लगे रहे। जाहिर है कि ये सभी आपबीती तथा आंखो देखी पीड़ा-व्यथाएं बिल्कुल सच्ची हैं। इनके अलावा, एक और सच, जिसे अब पूरी दुनिया जान और समझ चुकी है, वह यह कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी की 'ममता' अब तक नहीं जाग पाई है। जरा सोचिए, कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में हुई हिंसा में कम-से-कम 03 लोगों की जान चली गई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हालांकि, इस मामले में अब तक 300 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 1600 जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। हिंसा प्रभावित शमशेरगंज के एक निवासी हबीबउर रहमान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि बीएसएफ और सीआरपीएफकी तैनाती के बाद इलाके में माहौल शांत है। वैसे, खबरें यह भी आ रही हैं कि प्रशासन ने लोगों से दुकानें खोलने और अनुशासन बनाए रखने की बात कही है। वहीं, पीड़ित हिंदू परिवारों ने बीएसएफ की स्थायी तैनाती की मांग की है। उनके भीतर उस उग्र भीड़ का ऐसा खौफ समाया है कि उन्हें लगता है कि यदि बीएसएफ हटी तो फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी मृतकों और घायलों से मिलने उनके आंसू पोंछने के बजाए लगभग एक वर्ष के बाद होने वाले बंगाल चुनाव की गोटियां बिछाने में लगी हैं। जाहिर है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वह कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर इमामों से मिलने के बजाए मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के पीड़ित-प्रताड़ित, खौफजदां, बेबस और लाचार भुक्तभोगी परिवारों से मिलने, उनको मदद पहुंचाने और उनका दुःख-दर्द बांटने जातीं। यदि यह भी मान लें कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, तो कम-से-कम पीड़ितों को सांत्वना देने और ढाढ़स बंधाने के लिए वह अपना एक प्रतिनिधि ही भेज देतीं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। हां, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा उन्होंने अवश्य की है। बहरहाल, उक्त घटना के गर्भ से कुछ बेहद गंभीर सवाल उठे हैं, जो सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को कठघरे में खड़े करने की ताकत रखते हैं। जरा सोचिए, कि कहां तो हम बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते नहीं अघाते थे, लेकिन हम तो अपने ही घर बंगाल के हिंदुओं की रक्षा कर पाने में असमर्थ साबित होने लगे हैं। और तो और, अब जांच एजेंसियां बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की योजना तुर्की में बनाया गया था, जिसे बांग्लादेश के रास्ते बंगाल तक पहुंचाया गया। यह भी, कि इसके लिए बाकायदा 02 महीने पहले ही ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें पुलिस से बचकर दंगा भड़काने और स्थानीय मदरसों से मदद लेने की भी बातें शामिल हैं।

इस पर दो बेहद गंभीर सवाल बनते हैं। पहला, यह कि हम हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए किस मुह से यूनुस को दोष दें। उनसे कैसे कहें कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित और पीड़ित हैं, जबकि सच तो यह है कि हिंदू बंगाल में भी सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा सवाल, यह कि राज्य और केंद्र की हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं कि तुर्की में बनी और बांग्लादेश के रास्ते मुर्शिदाबाद तक पहुंची योजना को हम विफल नहीं कर पाए। जब हिंसा के दौरान बांग्लादेश से भारत में 71-150 कॉल किए गए, तब हमने उन्हें इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। वास्तव में ये कुछ सवाल हैं, जिनके उत्तर मिलना अभी शेष हैं। (इतिश्री)

धर्म को उसके मूल स्वरूप में ही लिया जाना चाहिए

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

धर्म के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव आदमी को आदमियत के प्रति आश्वस्त करता है। स्वाभाविक रूप से धर्म के प्रति आसक्ति के चलते आदमी कभी अनैतिक नहीं हो सकता। बशर्ते कि धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में अपने आचरण और व्यवहार में आत्मसात किया जाए। एक अर्थ में धार्मिक कट्टरता आदमी के अंतर्मन की असीम धर्मनिष्ठा को रेखांकित करती है। लेकिन, राजनीतिक कारणों के चलते 'धार्मिक कट्टरता' को एक अलग ही अर्थ में लिया जाने लगा है। यह आश्चर्यजनक है कि धर्म से धर्म का टकराव कैसे हो सकता है? आखिर धार्मिक प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है ? धर्म की ओट में राजनीति का गंदा खेल क्यों खेला जा रहा है ?

दरअसल ऐसे सुलगते सवाल लगातार विकृत होती राजनीति की देन है। वास्तव में होना यह चाहिए कि राजनीति हो तो विशुद्ध रूप से राजनीति ही हो और धर्म हो तो विशुद्ध रूप से धर्म ही हो। लेकिन हो यह रहा है कि एक दूसरे के क्षेत्र में एक-दूसरे का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र की राजनीति में व्यापक जनहित के प्रति समर्पित भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर धर्म में भी आत्म कल्याण के साथ-साथ जन कल्याण की भावना रहा करती है। ऐसी स्थिति में काफी हद तक दोनों के उद्देश्य में समानता दिखाई देती है। धर्म से धर्म की प्रतिस्पर्धा का तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन इसके उलट हो रहा है।

ऐसी स्थिति में जब अंतिम उद्देश्य लगभग एक समान हो, तो आखिर इसे लेकर व्यर्थ के टकराव की स्थिति निर्मित क्यों हो जाती है ? मूल रूप से कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के प्रतिकार की पैरवी नहीं करता। लेकिन धर्म की गलत तरह की व्याख्या के चलते ऐसी स्थिति निर्मित होने लग जाती है कि धर्म और राजनीति दोनों ही अपने मूल स्वरूप को खोने लगते हैं। परिणाम यह निकलता है कि विकृत मानसिकता का विस्तार समाज में अराजकता का वातावरण निर्मित कर देता है। जिसके चलते आए दिन कानून और व्यवस्था पर संकट आने लगता है। बेहतर तो यही है कि धर्म को धर्म रहने दिया जाए और राजनीति को राजनीति।

आम आदमी की धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक दृष्टि से भुनाने की मनोवृति एक प्रकार की तुच्छ राजनीति है। जिसके चलते धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसके आभामंडल पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। यही नहीं अपितु राजनीति भी विशुद्ध राजनीति नहीं होकर इतना विकृत स्वरूप धारण कर लेती है कि प्रबुद्ध एवं संभ्रांत वर्ग राजनीति से एक प्रकार की दूरी बना लेता है। इसके चलते राजनीति और भी अधिक बेलगाम होती चली जाती है। यदि धर्म को विशुद्ध रूप से आत्मसात करते हुए किसी भी क्षेत्र में सक्रियता का परिचय दिया जाए, तो निश्चित रूप से समूचे परिवेश में सात्विकता का वातावरण निर्मित होना चाहिए।

दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, यह आज से अधिक आने वाले कल में और अधिक चिंता का विषय हो सकता है। बेहतर हो यदि तमाम धर्म के व्याख्याकार अपने-अपने धर्म के सर्वमान्य मूलभूत सिद्धांतों को लिपिबद्ध करते हुए राष्ट्रीय चरित्र का अंग बनाएं। इसके चलते सामाजिक सद्भाव का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। अन्यथा अनावश्यक रूप से धर्म से धर्म का टकराव एक दूसरे को काफी हद तक हताहत कर देगा। ऐसी स्थिति में हमारी विश्व वंदनीय रही गौरवशाली संस्कृति इस कदर तहस नहस हो जाएगी कि धर्म के नाम पर अधर्म का वर्चस्व होगा और हम जंगल राज में जी रहे होंगे।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

गोविन्द सेन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बड़ों को उत्पात की छूट मिलनी चाहिए

चीजों को समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए. वैसे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है. हमेशा गर्मी, बारिश और ठण्ड नहीं रहती. समय के साथ आदमी बदलता है. भाषा बदलती है. रिश्ते बदलते हैं. फैशन भी बदलता है. अब देखिए कि एक जमाना था कि चौड़ी मोहरी के झाड़ूछाप बेलबाटम चलते थे. नाम ही था बेलबाटम यानी बेल जैसी बाटम हो जिसकी. फर्श पर चलो तो झाड़ू अपने आप लग जाती थी. आज वैसी पैंट कोई पहने तो कितना आउटडेटेड लगेगा. अब तो पेंसिलछाप स्किन टाइट पैंटें चलने लगी हैं. फैशन के नाम पर कितनी ही असुविधाएँ हँसते-हँसते झेल ली जाती हैं. कोई उफ़ तक नहीं करता. पहले ढीले कपड़ों का चलन था आजकल छोटे टाइट कपड़ों का चलन है. समय के साथ कपड़े ढीले-टाइट होते रहते हैं.

पहले कपड़ों पर क्रीज का खूब ख्याल रखा जाता था. पैंट पर खड़ी क्रीज होना जरूरी होता था. आज कपड़ों पर जितनी सलवटें हों उतना अच्छा माना जाता है. फटे हुए कपड़े नहीं पहने जाते थे. यदि नया कपड़ा खरीद नहीं पाते तो लोग फटी हुई जगह पर कारियाँ लगवा काम चलाते थे. रफू करवा लेते थे. अब तो फटे-फटाए कपड़ों का चलन है. फटी जींस शान से पहनी जाती है. घुटनों ही अनेक जगहों से जींस फटी होती है. कपड़ा फटा न हो तो फड़वा लिया जाता है. मुचड़े हुए कपड़े शान से पहने जाते हैं.

पहले कान बाल से ढके होते थे. आजकल कान और बालों का संपर्क मुश्किल से होता है. कटोरा कट बाल रखे जाते हैं. खोपड़ी के बीच के बाल बड़े रखे जाते हैं. पहले खोपड़ी पर चार बाल भी होते थे तो उन्हें खोपड़ी पर इस तरह फैलाया जाता था कि कोई यह न कहे कि सिर पर बिल्कुल बाल नहीं हैं. ये चार बाल हैं तो. दायीं या बायीं ओर के बचे हुए बालों से उभरे हुए चमकते रनवे को ढककर गंजत्व की रक्षा का जतन किया जाता था. लेकिन अब यह ढकोसला नहीं किया जाता बल्कि सीधे ही सिर मुंडा लिया जाता है. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. घोटमोट ही आज का फैशन है. समूची खोपड़ी ही बल्ब की तरह चमकती रहती है.

कुछ कहावतें बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं. उनमें कोई भी बदलाव ही नहीं हुआ है. उन्हें बदलने का समय आ गया है. आखिर पहले राजतंत्र था और अब प्रजातंत्र है. राजतंत्र के मुहावरे प्रजातंत्र में कैसे चलेंगे. हम शहरों के नाम कपड़ों की तरह बदल रहे हैं तो वही पुरानी कहावतें क्यों चलने दें. इसके लिए भी अभियान चलाया जाए.

कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था- 'अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं.' गंगाजी में कितना ही पानी बह गया है. कितने ही लोगों ने उसमें अपने कितने ही पाप धो लिए हैं. कितने ही मगरमच्छ मछलियों को निगलकर काल-कलवित हो चुके हैं. लेकिन कहावत वही चली आ रही है-'क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात.' कब तक बड़े ही छोटों के उत्पात को सहते रहेंगे. कब तक बड़े उन्हें क्षमा करते रहेंगे. अब तो बड़ों को उत्पात करने का मौका मिलना चाहिए. छोटों को भी क्षमा करने का गौरव मिलना चाहिए. वे बड़ों को क्षमा करें तो कितना मनोरम दृश्य उपस्थित होगा.

और ये होने भी लगा है. इसलिए अब इस कहावत को भी बदल देना चाहिए. उसे यूँ कर दें-क्षमा छोटन को चाहिए, बड़ेन को उत्पात. बड़े उत्पात करें और छोटे उन्हें क्षमा कर दें. छोटे की भलाई क्षमा करने में ही है. बड़ा तो उत्पात करता ही रहेगा. भले ही इसे जंगल का कानून कह लें लेकिन यही नए युग का नया संस्कार है. नए युग में पुराने सिक्के नहीं चलते।

विश्व धरोहर दिवस

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग,महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

विश्व धरोहरों का संरक्षण सांस्कृतिक जरूरत है

भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। भारतीय संविधान के विकास के साथ ही नीति निर्देशक तत्व भी विकसित हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद (आर्टिकल) 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों,स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वे इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करते रहें। राज्य के साथ साथ यह जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि वह पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, तालाब और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें। वर्तमान समय में यूनेस्को ने भारत में 43 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। विश्व धरोहर को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पहली संस्कृतिक धरोहर है और दूसरी प्राकृतिक धरोहर है। प्राकृतिक धरोहरों में झीलें,तालाब विभिन्न जल निकाय,वन क्षेत्र,विलुप्त होते जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को भी शामिल किया गया है।

विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस (World Heritage Day) जिसे प्रत्येक 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस की एक खास थीम भी निर्धारित करती है। वर्ष 2024 में विश्व धरोहर दिवस की थीम 'विविधता की खोज और अनुभव' (Discover and E&perience Diversity) थी जो हमारे इतिहास की समृद्धि पर प्रकाश डालती है और हमें विभिन्न समुदायों की अनूठी विरासत का पता लगाने और उसकी सराहना करने की याद दिलाती है। वही इस वर्ष 2025 की थीम 'आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत इंटरनेशनल कॉउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) की 60 वर्षों की तैयारी और सीख है'। जो धरोहर स्थलों की जर्जर होती स्थिति पर प्रकाश डालती है। फिर चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हो या मानवीय संघर्षों के कारण। इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजानों को संरक्षित और पुर्नस्थापित करने के लिए रणनीतियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। भारतीय संविधान के विकास के साथ ही नीति निर्देशक तत्व भी विकसित हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद (आर्टिकल) 49 जो ग्रीय महत्व के स्मारकों,स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वे इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करते रहें। राज्य के साथ साथ यह जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि वह पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन,झील,नदी,तालाब और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें। वर्तमान समय में यूनेस्को ने भारत में 43 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। विश्व धरोहर को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पहली संस्कृतिक धरोहर है और दूसरी प्राकृतिक धरोहर है। प्राकृतिक धरोहरों में झीलें,तालाब विभिन्न जल निकाय,वन क्षेत्र,विलुप्त होते जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को भी शामिल किया गया है। दोनों श्रेणियों की एक मिश्रित धरोहर भी इस सूची में शामिल हैं। वर्ष 1982 से प्रति वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसे 'इंटरनेशनल डे फ़ॉर मॉन्यूमेंट्स' भी कहा जाता है। यह नाम यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था 'इंटरनेशनल कॉउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (इकोसम) का दिया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर तथा उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। पृथ्वी एक निश्चित जलवायु तंत्र से संचालित है और इसमें परिवर्तन भी प्रत्येक स्थान की प्राकृतिक परिस्थिति के अनुसार होता रहता है लेकिन पिछली दो शताब्दियों से इस परिवर्तन की अत्यंत तेज गति से ग्रीनहाउस गैसों में हो रही वृद्धि ने जलवायु की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि का मुख्य कारण हमारी उत्पादन पद्धति और जीवन शैली है,जिसका प्रकृति के साथ प्रतिकूल संबंध है और इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर हो रहे इन जलवायु परिवर्तनों के कारण रोगवाहक कीटाणुओं में भी वृद्धि हो रही है और नए प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययनों का निष्कर्ष है कि वैश्विक तपन के कारण आने वाले पचास-साठ वर्षों में वनस्पति जगत और पशु जगत की प्रजातियों का लगभग चौथा हिस्सा लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। जलवायु परिवर्तन से एक ओर पारिस्थितिकीय असंतुलन से उत्पन्न खतरे के लिए जिम्मेदार है तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी इसके दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संसाधनों में कमी, कृषि उपज में कमी और जल का अभाव और भी अन्य वस्तुओं को

इसमें जोड़ा जा सकता है जो हमारे सामाजिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। जल आपूर्ति में वनों के विनाश एवं पहाड़ियों में भूस्खलन के कारण काफी कमी आ रही है। भू-गर्भीय जल को बहुत नीचे से खींचकर कृषि और उद्योगों में इस्तेमाल करने से इसके स्तर में कमी आ रही है। भूगर्भीय जल के खनन से भारत,चीन,पश्चिमी एशिया,रूस और अमेरिका के कई हिस्सों में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता अत्यंत बढ़ जाती है। प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण जीवन की बेहतरी के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक धरोहरों और संसाधनों के संरक्षण से ही हम अपने जीवन का संरक्षण भी कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध करा पाएंगे। जीवन के संरक्षण के साथ साथ ही जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राकृतिक धरोहर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है जो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक है। हमारे देश में धरोहरों की कोई कमी नहीं है सिर्फ उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहरें ही पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करतीं हैं और इनके आस पास के क्षेत्रों के लोगों को इनसे ही रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान विकास की अवधारणा के बरक्स टिकाऊ/सतत विकास की अवधारणा को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है जिसका ध्येय प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम अपव्यय करना और आने वाली पीढ़ी के लिए टिकाऊ व्यवस्था प्रदान करना है। टिकाऊ विकास की व्यवस्था में मनुष्य को प्रकृति का एक अविभाज्य अंग माना गया है। यह व्यवस्था ओपन सिस्टम को आधारभूत मानती है और संकीर्ण,मानव - केंद्रित दृष्टिकोण को नकारती है। विकास की वर्तमान व्यवस्था में मनुष्य को होमो इकोनॉमिक्स अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि समझने वाला प्राणी माना गया है लेकिन सतत विकास की व्यवस्था में मनुष्य को नीतिनिष्ठ होने और आर्थिक लाभ हानि से ऊपर उठकर मानवीय संबंधों का सम्मान करने वाला चेतना से संपन्न प्राणी समझा गया है। सतत विकास की व्यवस्था में मांग और आवश्यकताओं में भी अंतर किया गया है। कृत्रिम मांग को नकारा गया है और आवश्यकताओं पर भी नियंत्रण रखने पर जोर दिया गया है। इस व्यवस्था में मानवीय श्रम के महत्व को भी उजागर किया गया है और साथ ही मशीनीकरण की समस्याओं और जटिलताओं का भी उल्लेख किया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी जोर दिया जा रहा है। विश्व के बहुत से देशों में वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनमें अमेरिका में कैलिफोर्निया,मैसेचुयेट्स,फिनलैंड, स्पेन,पुर्तगाल तथा यूरोपीय संसद ने भी वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विश्व धरोहर के संरक्षण के मामले में हम जिस पहल में आगे रहे हैं वह है कानून और नियम बनाना लेकिन यह भी देखा जाना आवश्यक है कि वे कानून और नियम प्रभावी हैं या नहीं यदि हैं तो ठीक तरह से काम कर रहे है या नहीं,साथ ही लोगों को यह स्वीकार्य है या नहीं यह भी जानना जरूरी है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को लेकर एक संपूर्ण दृष्टि का विकास करना आवश्यक है और धरोहरों को आजीविका के साथ जोड़ने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 18 अप्रैल को दुनिया भर के लोग विश्व धरोहर दिवस मनाने के लिए एकजुट होते हैं। यह एक विशेष दिन है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। इस दिन प्राचीन मंदिरों, मकबरों, ऐतिहासिक स्मारकों,पुरातात्विक स्थलों का सम्मान किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मानव इतिहास और प्रकृति के इन अपूरणीय खजानों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए।

गुड फ्राइडे विशेष

श्वेता गोयल

(लेखिका डेढ़ दशक से शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हैं)

मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक है गुड फ्राइडे

गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो न केवल ईसा मसीह के बलिदान की स्मृति का प्रतीक है बल्कि मानवता, क्षमा, प्रेम और त्याग जैसे मूलभूत सिद्धांतों की पुकार भी है। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब ईसा मसीह को अन्यायपूर्ण ढ़ंग से सूली पर चढ़ा दिया गया था। गुड फ्राइडे, जिसे 'होली फ्राइडे', 'ब्लैक फ्राइडे' या 'ग्रेट फ्राइडे' के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार, यह वही दिन है, जब प्रभु यीशु ने मानवता के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह एकमात्र ऐसा पर्व है, जिसकी तिथि यहूदी पंचांग के अनुसार चांद देखकर निर्धारित होती है और यह हर वर्ष ईसाई समुदाय द्वारा पवित्र सप्ताह के अंतर्गत श्रद्धा और शोक के भाव से मनाया जाता है।

गुड फ्राइडे को उस महान बलिदान की स्मृति के रूप में देखा जाता है, जब यीशु मसीह ने मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए स्वयं को मृत्यु के हवाले कर दिया था। उन्हें केवल इसलिए क्रूस पर लटकाकर मारा गया क्योंकि वे उस समय के धार्मिक अंधविश्वासों, अन्याय और कट्टरपंथ के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। वे प्रेम, करूणा, क्षमा और सत्य के प्रचारक थे और इन गुणों को अपनाकर समाज को जागरूक बना रहे थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि सबको सत्य, अहिंसा, परोपकार और सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा दी। वे सदैव शांति, एकता और मानवीय मूल्यों के पोषक रहे, जिनकी शिक्षाएं सीमाओं में बंधी नहीं थी बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए थी।

ईसा मसीह ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है लेकिन यही मार्ग सच्चे परिवर्तन का वाहक है। उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंडों और धार्मिक ढ़ोंगियों का विरोध किया, जिसके कारण वे कट्टरपंथी धर्मगुरुओं की आंखों की किरकिरी बन गए। ईसा की लोकप्रियता और उनकी शिक्षाओं के प्रति आमजन का बढ़ता झुकाव उस समय के धार्मिक ठेकेदारों को असहज करने लगा। लोगों ने उन धर्मगुरुओं के बजाय ईसा मसीह की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उनका प्रभाव कमजोर होने लगा। इस असहजता के चलते यहूदियों के धार्मिक कट्टरपंथियों ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंतियुस पिलातुस से मृत्युदंड की मांग कर दी। पिलातुस को भी डर था कि कहीं यहूदी विद्रोह न कर दें, अतः उसने धार्मिक भावना को शांत करने के लिए ईसा को सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड से पहले उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और अपने ही कंधों पर भारी लकड़ी की क्रॉस उठाकर 'गोल गोथा' नामक स्थान तक ले जाने को मजबूर किया गया। वहां उन्हें दो अन्य अपराधियों के साथ क्रूस पर कीलों से ठोककर लटका दिया गया।

ईसा ने अपनी अंतिम सांसें शुक्रवार के दिन ली और इसी दिन को 'गुड फ्राइडे' के रूप में जाना जाता है लेकिन यह दिन केवल उनकी मृत्यु की याद भर नहीं है बल्कि यह उस सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिसमें निहित है क्षमा, त्याग और मानवता की पराकाष्ठा। जिस समय वे अपने प्राण त्याग रहे थे, उन्होंने अपने हत्यारों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहा था, 'हे परमपिता! इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।' गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय चर्चों में एकत्र होता है, जहां विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। इस दिन चर्चों में घंटा नहीं बजाया जाता बल्कि लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं। लोग काले वस्त्र पहनते हैं, क्रॉस को चूमते हैं और प्रभु यीशु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर लोग उपवास रखते हैं, लौकिक सुख-सुविधाओं का त्याग करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। गिरिजाघरों और घरों से सजावटी वस्तुएं हटा दी जाती हैं या उन्हें कपड़े से ढ़क दिया जाता है। प्रार्थना का समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच का होता है क्योंकि मान्यता है कि इसी समय ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। इस दौरान उनके 'सात वाक्य' विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं, जो क्षमा, मेल, त्याग और दया का भाव लिए हुए हैं। इन्हीं वाक्यों में उनके अध्यात्म और मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले 'राख बुधवार' से ईसाई समुदाय में उपवास और प्रार्थनाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। यह उपवास, जिसे 'लेंट' कहा जाता है, ईसा मसीह के उस चालीस दिन के उपवास की स्मृति में रखा जाता है, जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने से पूर्व आत्मचिंतन और तपस्या की थी। इस अवधि में लोग मांसाहार और विलासिता का त्याग करते हैं और सादा व सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यह परम्परा न केवल धार्मिक अनुशासन का अभ्यास है बल्कि आत्मशुद्धि और सेवा भावना को जगाने का माध्यम भी है। गुड फ्राइडे के दिन चर्चों में दान देने की परम्परा भी है ताकि समाज सेवा के कार्यों को बल मिले। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह केवल एक महान संत या गुरु नहीं थे, वे परमेश्वर के पुत्र थे, जिन्हें मानव जाति को पापों से मुक्त करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपने उपदेशों में न केवल जीवन के मूल्यों के बारे में बताया बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीकर उदाहरण भी प्रस्तुत किया। वे स्वयं दीन-हीन, रोगियों और पापियों के साथ समय बिताते थे, उन्हें प्रेम देते थे और उनकी सेवा करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि थी। वे अपने बलिदान से यह स्पष्ट संदेश देना चाहते थे कि प्रेम, क्षमा और त्याग से ही मानवता का कल्याण संभव है।

गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर संडे आता है, जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूली पर मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को वे पुनः जीवित हो गए थे। इस दिन को ईसाई समुदाय अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाता है, चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं, प्रभु भोज का आयोजन होता है और यीशु के पुनरुत्थान की कथा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि वे जीवित होकर अपने शिष्यों के साथ चालीस दिनों तक रहे और हजारों लोगों को दर्शन दिए। सबसे पहले मरियम मदीलिनी नामक महिला ने उन्हें देखा और यह शुभ समाचार अन्य लोगों को दिया। यही कारण है कि ईस्टर की सुबह महिलाएं विशेष आराधना करती हैं। ईसा मसीह के जीवन की यह कथा केवल ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है। उनके विचार, शिक्षाएं और बलिदान सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे केवल ईसाइयों के आराध्य नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के आदर्श हैं, जो प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और मानवता में विश्वास रखता है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चाई, भलाई और मानव कल्याण की राह चाहे जितनी भी कठिन हो, उस पर चलने से ही सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। प्रभु यीशु का जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महान शिक्षाशास्त्र है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना दो हजार वर्ष पूर्व था। यही कारण है कि गुड फ्राइडे आज भी न केवल एक धर्म विशेष का पर्व है बल्कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक है।

पुस्तक चर्चा

राकेश अचल

समीक्षक

अद्भुत है 'कश्तियों वाला सफ़र'

हमारे मध्यप्रदेश की आत्मा कविवर सत्यमोहन वर्मा को कविता लिखते जितना वक्त हो चुका है उतनी मेरी उम्र भी शायद न हो। उनके बारे में हमारे काव्य पूर्वज दिनकर सोनवलकर हों या प्रो. सरोजकुमार या डॉ. कुंवर बैचेन जो लिख चुके हैं उससे आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, किन्तु जब एक पाठक और कविता के छात्र के रूप में मैं 'कश्तियों वाला सफ़र ' से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भीतर से आंदोलित हो रहा हूँ। मेरे भीतर जो हलचल इस संग्रह को पढ़कर हुई है उसे आप समीक्षा बिलकुल न कहिये।

कुल 72 गजलों के इस अंतिम संग्रह को मैं वर्मा जी का अंतिम संग्रह नहीं मानता हालाँकि वे कहते हैं -

सबका चुका दिया है मैने हिसाब यारों,
अब बंद कर रहा हूँ अपनी किताब यारों।

मेरा अपना अनुभवव है कि अनुभवों कि किताब कभी बंद नहीं होती, कवि की आँखें बंद होने के बाद भी वो खुली रहती है और अनेक वर्षों तक आने वाली पीढीको रास्ता दिखाती रहती हैं। कविवर वर्मा जी कि गजलें भी यही काम करती दिखाई देती हैं। 92 साल के सुदीर्घ जीवन के अनुभव जब कविता के किसी भी स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे मन्त्र बन जाते हैं। इन्हें समझना,साधना आसान बात नहीं है। मैं भी एक तुकबंद कवि हूँ इसलिए इस बात को औरों से ज्यादा समझता हूँ।

कश्तियों वाले सफ़र से पहले हम और आप वर्मा जी के अनेक संकलनों से गुजर चुके हैं वर्मा जी केवल कवि नहीं हैं बल्कि अभिव्यक्ति कि अनेक विधाओं के मर्मज्ञ हैं इसीलिए उनकी कविताएं सम्पूर्ण है। वे हिंदी के छंद जानते हैं तो उर्दू गजलों का अनुशासन भी । वे लोक का ककहरा समझते हैं तो मंच की गरिमा भी। इसीलिए जब वे गजल कहते हैं तो वो किसी परम्परा से बंधी गजल नहीं होती बल्कि अपने आप में एक परम्परा होती है।

उनकी एक गजल मुलाहिजा कीजिये -

पीर ने गौतम बनाया और जी भर आजमाया
दर्द की सौदागरी में अपने घावों को छुपाया

समाज की विसंगतियों,विद्रूपताओं, विडंबनाओं को वे इतनी आसानी से इंगित करते हैं कि हैरानी होती है। बिना किसी कारीगरी के महीन से महीन कातना कोई वर्मा जी से सीख सकता है। वे कहते हैं

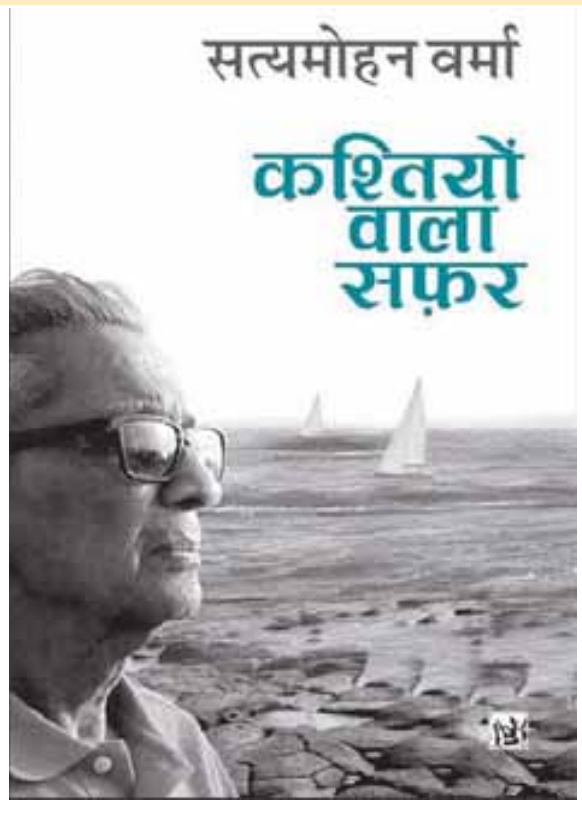

इक और नई अदा है मेरे मेहरबान की
उसने भी हदें खींच लीं अपने मकान की

वर्मा जी अपनी बात कहते हुए न भाषा के आग्रही हैं और न व्याकरण के। वे हर औजार का इस्तेमाल आवश्यकतानुसार करते हैं और जमकर करते है। उर्दू वाले अगर 'मिरा' लिखते हैं तो वर्मा जी 'मेरा' लिखते हैं। उन्हें हिंदी,उर्दू ,फ़ारसी या बुंदेली से शब्द लेते वक्त कोई संकोच नहीं होत। वे कभी एकांगी होते हैं तो कभी समग्र की बात करने लागते है। उनकी गजलों में साहस भी है और दुस्साहस भी। संवेदना भी है और आक्रोश भी,प्रेम भी है और करुणा भी।

आसमां के ठौर से मेघों का डेरा ले गया
जाने किसके वास्ते बादल घनेरा ले गया

अब यहां मेघ भी हैं और बादल भी। डेरा भी है और घनेरा भी। इसी भाषायी 'कॉकटेल' ने वर्मा जी कि हर गजल को सुस्वाद बना दिया है। बस पढ़ते जाइये...पढ़ते जाइये। वर्मा जी को ठहर -ठहर के पढ़ना पड़ता है। वे अपने रचना संसार में एक विस्तृत कैनवास लेकर निकलते हैं। मेरी बे-बहर गजलों को वर्मा जी का आशीर्वाद जब-तब मिलता रहता है। वे जब मेरी किसी गजल को अपना आशीर्वाद देते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली,लेकिन वर्म जी की गजलें ऐसी हैं जो किसी परीक्षा से नहीं अपितु जीवन कि भट्टी में अग्निपरीक्षा से गुजरी हुई हैं। उनकी आभा कंचन जैसी है।

संग्रह कि पहली गजल का पहला शेर ही संग्रह के बारे में और उनके अपने बारे में सब कुछ कह देता है। ये शेर ही एक वक्तव्य है।

कश्तियों वाला सफ़र था और हम थे
नाखुदाओं का भी डर था और हम थे

वर्मा जी ने जिस तन्मयता से लिखा है उसी लगन से लोकभारती प्रकाशन (प्रयागराज) ने 'कश्तियों वाला सफ़र' छापा भी है। बधाई प्रकाशक को भी और लेखक का तो अभिनंदन बनता ही है। हालाँकि मेरा निजी विचार है कि 72 गजलों को पढ़ने के लिए संग्रह की कीमत (395 रूपये) बहुत ज्यादा है। आज जब पाठक महंगी किताबों कि वजह से पढ़ने से कतराने लगा है तब ये संग्रह यदि कुछ सस्ता होता तो बेहतर होता। यदि आप गजलें पढ़ने में दिलचस्बी रखते हैं तो आपका कुतुबखाना बिना 'कश्तियों वाला सफ़र' के अधूरा है।

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव की मौजूदगी में प्रारंभ होगी कार्यशाला

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुर्नस्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय-आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शुक्रवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर मंथन होगा। कार्यशाला में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह स्वागत उद्बोधन देंगे। दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की रूपरेखा डॉ. राहुल मूँगीकर प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति भी दी जाएगी।

प्रमुख विषय - वन संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रबंधन- राष्ट्रीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएं, उनकी सीमाएं और समाधान, जैव विविधता संशोधन अधिनियम-2023, सामुदायिक वन अधिकार, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और वन पुर्नस्थापन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैंगलुरू से आ रहे प्रो. रमेश विशेषज्ञ वक्तव्य भी देंगे। कार्यशाला में डॉ. योगेश गोखले, डॉ. राजेन्द्र दहातोंडे आदि वक्ता विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे।

राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन राज्यपाल श्री पटेल समापन सत्र को करेंगे संबोधित- राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल राष्ट्रीय कार्य शाला के समापन-सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व राष्ट्रीय जनजातीय आयोग अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान समापन वक्तव्य देंगे।

कार्यशाला में वनीकरण, जलवायु संवेदनशीलता और वनवासी समुदायों की समावेशी भागीदारी पर केन्द्रित डॉक्युमेंट्री फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला वनों, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और जनजातीय आजीविका को केंद्र में रखते हुए एक सतत और न्यायसंगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सांभर का शिकार करती बाघिन ने रोमांचित किया पर्यटकों को

उमरिया (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक रोमांचक दृश्य देखने को मिला। ताला जोन के चक्रधरा एरिया में सिद्ध बाबा नाम की लगभग सात वर्षीय बाघिन ने सांभर का शिकार किया। घटना उस समय हुई जब पर्यटक जंगल सफारी पर थे। बाघिन नाले के पास झाड़ियों में छिपी बैठी थी। इसी दौरान सांभर का एक झुंड नाले में पानी पीने आया। बाघिन ने मौका देखते ही झाड़ियों से निकलकर सांभर पर छलांग लगा दी। वह सांभर को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर चली गई।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 165 से अधिक बाघ और बाघिन हैं। सिद्ध बाबा बाघिन अक्सर इस क्षेत्र में अपने शावकों के साथ दिखाई देती है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। यह वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पर्यटकों के लिए यह एक यादगार नजारा बन गया।

क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा एमडी ड्रग्स का मुख्य सप्लायर

इंदौर (नप्र)। क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के डग से ड्रग तस्कर अय्यूब खान (49) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 21 ग्राम एमडी बरामद की गई है। अय्यूब पर 13 अपराध दर्ज हैं। उस पर दस हजार रुपए का इनाम था। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, टीम को सूचना मिली कि एमआर-10 ब्रीच के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। मौके पर टीम पहुंची तो पुलिस को देख वह भागने लगा। उसे घेराबंदी कर पकड़ा।

पूछताछ में उसने अपना नाम अय्यूब खान उर्फ अय्यूब लाला बताया। उसके पास करीब दो लाख रुपए की 21 ग्राम एमडी मिली। आरोपी ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। वह इंदौर के पैडलर्स को भी ड्रग सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच ने पूर्व में 52 ग्राम एमडी ड्रग के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें भी अय्यूब ने ही ड्रग सप्लाई की थी। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में पकड़ाए आरोपियों से अय्यूब की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी।

जबलपुर में बिना अनुमति चल रहा हॉस्पिटल

बीएएमएस डॉक्टर कर रहा था एलोपैथिक इलाज, एसडीएम ने सील कर थाने में की शिकायत

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को बिलहरी क्षेत्र में फर्जी डिग्री और बिना अनुमति के संचालित हो रहे एक अस्पताल पर कार्रवाई की। रांझी एसडीएम आरएस मरावी ने गरुड़ दल के साथ मौके पर छापा मारा। इस दौरान डॉक्टर दिव्यांश सुलखिया द्वारा संचालित 'सुलखिया हॉस्पिटल' को बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। मौके से एलोपैथिक दवाइयां और इलाज के सबूत मिलने के बाद अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया।

एसडीएम आरएस मरावी ने बताया जांच के दौरान अस्पताल में 10 बेड, नर्सिंग स्टाफ और इलाजरत मरीज मिले। डॉक्टर दिव्यांश खुद मरीजों को एलोपैथिक दवाएं दे रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बीएएमएस(आयुर्वेद) की डिग्री

होना बताया, लेकिन एलोपैथी पद्धति से इलाज कर रहे थे। जब दस्तावेज मांगे गए तो अस्पताल के संचालन से जुड़ी कोई अनुमति या रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं था।

मौके पर मौजूद टीम को वहां भर्ती मरीज मिले। मरीजों ने बताया कि वे लंबे समय से यहां इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी यह जानकारी नहीं मिली कि डॉक्टर एलोपैथी की विधिवत योग्यता नहीं रखते। एक मरीज ने बताया कि यहां रोजाना 20 से 25 मरीज इलाज के लिए आते हैं और कई को भर्ती भी किया जाता है।

जांच में अस्पताल के अंदर डॉक्टर का केबिन, पलंग, दवाइयां, और स्टाफ सक्रिय रूप से काम करता मिला। जब टीम ने पूछताछ शुरू की तो डॉक्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। गरुड़ दल ने मौके से एलोपैथिक दवाइयों के कई पैकेट जब्त किए। कार्रवाई के बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और डॉक्टर दिव्यांश सुलखिया के खिलाफ गोरा बाजार थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है।

एसडीएम आरएस मरावी ने कहा कि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के चल रहे अस्पतालों और क्लीनिकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

शाजापुर में 225 हिंदू और 16 मुस्लिम जोड़ों की शादी

बारात में बजे 200 ढोल, बैंड-बाजे की धुन पर जमकर नाचे बाराती

शाजापुर (नप्र)। शाजापुर जिले के बेरछा मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में 225 जोड़ों का विवाह और 16

जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। जनपद पंचायत शाजापुर ने पटेल ऑयल मिल प्रांगण में इस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में 200 से अधिक ढोल और बैंड बाजों की धुनों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस अवसर पर सामूहिक बारात का आयोजन भी किया गया। यह बारात आयोजन स्थल से प्रारंभ होकर नजर अली मार्ग से होता हुआ मां प्रभावेश्वरी माता मंदिर पहुंची। फिर रेलवे प्रांगण और प्रशांत तिराहे से होते हुए वापस आयोजन स्थल पर समाप्त हुई। नगर के व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने कई स्थानों पर बारात का स्वागत किया।

रायसेन के बरुखार जंगल में दिखा टाइगर

शादी में जाते वक्त किसान ने बनाया वीडियो, सड़क किनारे खड़ा था बाघ

रायसेन (नप्र)। रायसेन जिले के बरुखार के जंगल क्षेत्र में एक बार फिर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। ग्राम सदालतपुर निवासी किसान अनीस पटेल ने शादी समारोह में जाते समय मुख्य सड़क किनारे खड़े बाघ का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया।वीडियो में साफ देखा जा सका है कि बाघ सड़क किनारे खड़ा है और आसपास कोई डर या हलचल महसूस नहीं कर रहा।

बरुखार और चिकलोद के वन क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से बाघों की लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं। मुख्य सड़क के आसपास इनकी चहलकदमी अब स्थानीय लोगों के लिए सामान्य दृश्य बनता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल भी बना हुआ है।

दो बाघों का हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन- कुछ ही दिन पहले भोजपुर मंदिर के समीप जंगल क्षेत्र से दो बाघों का सफल रेस्क्यू किया गया था। इस ऑपरेशन को वन विहार भोपाल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया था।

इस दौरान एक बाघ को पिंजरे में पकड़कर, जबकि दूसरे को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर कब्जे में लिया गया। इसके बाद दोनों बाघों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थानांतरित किया गया है।

राजगढ़ में गेहूं खरीदी केंद्र पर तुलाई में हेराफेरी

मंत्री ने पकड़ा प्रति बोरी 150 ग्राम का फर्जीवाड़ा, 4 क्विंटल गेहूं जब्त

राजगढ़ (भोपाल) (नप्र)। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री नारायण सिंह पंवार ने शुक्रवार को राजगढ़ जिले के नापानेरा गेहूं उपार्जन केंद्र पर औचक निरीक्षण कर बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रत्येक बोरी में 150 ग्राम गेहूं की कम तौल की जा रही थी, जिससे किसानों को सीधा नुकसान हो रहा था।

हर बोरी पर 150 ग्राम का हेराफेरी- निरीक्षण में सामने आया कि बारदाने का वास्तविक वजन 500 ग्राम होने के बावजूद 650 ग्राम दर्ज किया जा रहा था, जिससे हर बोरी में किसान को 150 ग्राम गेहूं कम तौला जा रहा था।

अब तक इस केंद्र पर 20,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है, यानी हजारों किलो गेहूं की हेराफेरी की आशंका है।

4 क्विंटल गेहूं जब्त, कलेक्टर को दिए कड़े निर्देश- मंत्री पंवार ने मौके से करीब 4 क्विंटल गेहूं जब्त किया, जिसकी तौल में गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया

कि इस मामले में तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।मंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री बोले- मैं खुद किसान का बेटा हूं- मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की मेहनत की एक-एक बूंद की कीमत हम जानते हैं और किसी भी स्तर पर उन्हें लूटने नहीं देंगे।

ये रहे मौजूद- निरीक्षण के दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा, साथ ही कई अधिकारी और स्थानीय किसान मौजूद रहे।

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ कैडर के 25 अफसरों के तबादले

प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर और चीफ कमिश्नर के ट्रांसफर

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के अफसरों को थोकबंद तबादले किए हैं। इसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी 17 अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग द्वारा सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) में किए गए स्थानांतरण के बाद एमपी-सीजी में 8 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर किए गए अफसरों में प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स स्तर के अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के जो अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। उसमें अंजू अरोरा पीसीआईटी भोपाल के एक विंग से दूसरे जोन में गई हैं। इसके अलावा राहुल रमन पीसीआईटी इंदौर के एक विंग से दूसरे विंग में इंदौर में ही भेजे गए हैं। सुनील कुमार सिंह को रायपुर में एक विंग से दूसरे विंग में भेजा गया है। किशोर बी को दिल्ली से भोपाल पीसीआईटी सेंट्रल बनाकर भेजा गया है। वहीं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स प्रदीप हेडाऊ ओएसडी से इंदौर सीसीआईटी बनाकर भेजे गए हैं। इनके अलावा राजाराम शाह को दिल्ली से पीसीआईटी उज्जैन, माया माहेश्वरी को पीआर एडीजी (एनएडीटी आरसी)भोपाल से पीसीआईटी मुंबई भेजा गया है। सुखवीर चौधरी पीसीआईटी गुवाहाटी से पीसीआईटी ग्वालियर और मुनीश कुमार पीसीआईटी रायपुर पदस्थ किए गए हैं। श्रुजनी मोहंती को एडीजी भोपाल पदस्थ किया गया है। साथ ही कोलाकलूरी रवि किरन पीडीआईटी रायपुर बनाए गए हैं। इनके साथ ही राम तिवारी सीआईटी रायपुर, शिंदे सुधाकर नामदेव डीआईटी भोपाल और रघुनाथ सीआईटी भोपाल पदस्थ किए गए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जिन अफसरों को ट्रांसफर किए गए हैं। उनमें अनूप सिंह, भोपाल, योगेश कुमार शर्मा, ग्वालियर, श्रवण कुमार मीना रायपुर से जबलपुर, विजय कुमार सिंह इंदौर से अहमदाबाद, भारती महाजन सिंह भोपाल से भोपाल (विंग बदली), गरिमा चौधरी भोपाल से कानपुर, राजेश कुमार भोपाल से भोपाल (विंग बदली), रामकुमार यादव इंदौर से भोपाल पदस्थ किए गए हैं। ये सभी अधिकारी सीआईटी कैडर के हैं।

पंचायतें विकसित होंगी तभी विकसित रीवा का सपना साकार होगा : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद पंच-सरपंचों से संवाद का स्वागत योग्य अवसर आया है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री पटेल की पहल से ग्राम पंचायतों के विकास को गति मिलेगी। ग्राम पंचायतों का विकास होगा तभी रीवा का विकास संभव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांव के विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रदान कर रहे हैं। रीवा जिले में केवल जल जीवन मिशन से ही तीन हजार करोड़ रुपए के निर्माण कार्य मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा आवास प्लस का 98 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। जिले में लाखों गरीब परिवारों को इनसे पक्के आवास मिले हैं। बेसहारा गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। गौशाला में प्रत्येक गाय के लिए प्रतिदिन 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 3500 डॉक्टरों और 10 हजार चिकित्सा कर्मियों की भर्ती इस माह अक्टूबर माह तक पूरी कर ली जाएगी। उप स्वास्थ्य केन्द्र तक टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। पंचायत पदाधिकारियों की जो कठिनाईयाँ हैं उन्हें हल करके पंचायतों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल के मुख्य आतिथ्य में पंच-सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर पंच परमेश्वर की कल्पना की थी। राष्ट्रपिता की परिकल्पना में पंचायतों का कर्तव्य महत्पूर्ण था। पंचायत राज अधिनियम में कर्तव्यों के स्थान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों को बल दिया गया। पंचायत पदाधिकारी अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान दें। विवाद और झगड़े से विकास के कार्य संभव नहीं हैं। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर और प्रशासनिक व्यवस्था से समन्वय बनाकर ही पंचायतों का विकास होगा। ग्राम पंचायतों को गांव की साफ-सफाई, सड़कों के निर्माण, कचरा प्रबंधन, गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शिक्षा के विकास, जल संरक्षण के कार्य तथा सामाजिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। जब हम आम नागरिकों को सुविधाएं देंगे तो व्यवस्था बनाने के लिए टैक्स भी लगाना होगा। पंचायत पदाधिकारियों से मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत की वास्तविकताओं का मुझे पूरा एहसास है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरपंचों की 15 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग में हर पंचायत को पर्याप्त राशि दी जा रही है। राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। पंचायतों में अब राशि की कोई कमी नहीं है। हम जिस तरह अपने परिवार का वित्तीय प्रबंधन करते हैं उसी तरह ग्राम पंचायत का भी वित्तीय प्रबंधन करना होगा।

जल गंगा संवर्धन अभियान

पलकमती नदी में बोरी बंधान स्वच्छता दूतों का सम्मान

सुबह सवेरे सोहागपुर। क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के सानिध्य में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ,समाजसेवियों एवं क्षेत्र के नागरिकों ने पलकमती नदी में दो स्थानों पर बोरी बंधान बनाने के लिए श्रमदान किया । उल्लेखनीय है कि 30 मार्च से प्रारंभ हुए 'जल गंगा जल संवर्धन अभियान' का समापन 30 जून को होगा। इस अभियान की थीम 'जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण' रखा गया है। इसी तारतम्य में सैंकड़ो नागरिकों ने श्रमदान के लिए पलकमती नदी में उतर कर पलकमती रिपटे के पास बोरी बंधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया । जिसमें अंबेडकर वार्ड एवं रामप्रसाद वार्ड के दोनो किनारों के बीच पानी रोकने एवं जल स्तर बनाए रखने के लिए बोरी बंधान की शुरुआत की गई। इस अभियान में पलकमती नदी की सफाई एवं गहरीकरण के लिए जेसीबी मशीन, ट्रेक्टर आदि की सहायता ली गई। इस अभियान में नगर पंचायत परिषद, राजस्व ,शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, विद्युत मंडल, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नागरिक कार्यक्रम में जु श्रमदान किया। इसी क्रम में क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने श्रमदान कार्यक्रम के मध्य नदी में नगर परिषद के स्वच्छता दूतों का सम्मान किया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, अनुविभागीय अधिकारी अनिल कुमार जैन उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, प्रभारी तहसीलदार आर . के. झरबड़े, नगर पालिका अधिकारी जी .एस .राजपूत, उपयंत्री रामगोपाल चौबे, सीईओ संजय अग्रवाल, बीएमओ संदीप केरकेट्टा , वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी, बीआरसी राकेश रघुवंशी, बीईओ राज, प्रतिपाल सिंह खनूजा, डॉ संजीव शुक्ला,भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्विनी सरोज, पार्षद कविता साहू , विकासखंड खेल समन्वयक चंदा दुबे, अधिवक्ता गण, व्यापारी गण, नगर पंचायत परिषद के कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

एम्स भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग ने मनाया स्थापना दिवस समारोह

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग की उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से औषधियों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया। फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. बालाकृष्णन एस. ने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बीते वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने फार्माकोविजिलेंस (औषधि सुरक्षा निगरानी), मटेरियोविजिलेंस (चिकित्सा उपकरण सुरक्षा निगरानी), प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट (नुस्खा जांच), आउटरीच गतिविधियों (जन जागरूकता कार्यक्रम) और राष्ट्रीय फार्मक्रिज़ (ज्ञान प्रतियोगिता) जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से विभाग की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025, विभाग का प्रथम न्यूज़लेटर, और 30 मौखिक व पोस्टर प्रस्तुतियाँ उल्लेखनीय रही।

फार्माकोलॉजी विभाग के डॉ. अजय शुक्ला और डॉ. अहमद नाजमी को उनके इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स के लिए सम्मानित किया गया। प्रो. (डॉ.) शिल्पा कौर को 2024 में एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में मौखिक प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। डॉ. ऋषिका को उनके थीसिस हेतु ICMR पुरस्कार और डॉ. गोकुल को शोध के लिए इंट्राम्यूरल ग्रांट प्राप्त हुआ। फैकल्टी प्रो. (डॉ.) रतींदर झाज को ISoP 2024, कनाडा में इको-फार्माकोविजिलेंस पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। डॉ. शुभम अटल को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बॉस्टन में डिप्रेशन में प्रिसीजन मेडिसिन पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। विभाग ने शैक्षिक विस्तार में भी प्रगति की है, जिसमें पीएचडी स्कॉलर और डीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नामांकन में वृद्धि शामिल है।

एम्स भोपाल के चिकित्सकों को मेडिकस एक्सीलेंस ऑनर रोल पुरस्कार से सम्मानित

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह संस्थान में शैक्षणिक श्रेष्ठता और ज्ञान के आदान-प्रदान को एक प्रेरक परंपरा के रूप में विकसित कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से संकाय सदस्य और छात्र निरंतर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में, एम्स भोपाल के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की डॉ. भूपेश्वरी पटेल (अतिरिक्त प्रोफेसर) एवं डॉ. रश्मि वर्मा (सहायक प्रोफेसर) को मेडिकस एक्सीलेंस ऑनर रोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा लखनऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन COMET-2025 (कॉन्क्लेव ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज़ एंड ट्रॉमा) में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन विशिष्ट परास्नातक चिकित्सकों को दिया जाता है जिन्होंने आपातकालीन चिकित्सा और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, यूनाइटेड किंगडम, अबूधाबी, सऊदी अरब, नेपाल समेत विश्वभर के आपातकालीन चिकित्सा एवं ट्रॉमा विशेषज्ञों ने भाग लिया।

कांग्रेस संगठन एक विचार है जो आजादी के पहले से हर दिल में बसा है : हरीश चौधरी

बुंदेलखंड के विकास के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने 1100 करोड़ दिये थे, लेकिन सब भाजपा नेता डकार गये- जीतू पटवारी

भोपाल। मप्र कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी (विधायक) और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्धारित दौरा कार्यक्रमानुसार आज प्रात ओरछा में रामराजा दरबार के दर्शन, पूजा-अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुखहाली की कामना की। तत्पष्चात नेताद्वय पृथ्वीपुर पहुंचे जहां निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर विधानससभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर, प्रवक्ता श्रीमती रोशनी यादव की मौजूदगी में निवाड़ी में मप्र के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा जी ने भाजपा की सदस्याता छोड़ मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के समक्ष अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेताद्वय ने दोपहर बाद टीकमगढ़ पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय नेताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की। बैठक के दौरान स्थानीय नेताओं द्वारा श्री चौधरी और श्री पटवारी का मिष्ठान से तुलादान किया गया।

मप्र प्रभारी श्री हरीश चौधरी ने कहा कि संगठन का सृजन विचार, विचारधारा अथवा व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है, जो संगठन को आगे लेकर जाता है। कांग्रेस पार्टी के नाते संगठन में रहते हुये कांग्रेस के विचार को जन-जन तक पहुंचाने का पैमान हर कार्यकर्ता का होना चाहिए। देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में रह रहे प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता, शिक्षा, भोजन का अधिकार देना और इसके लिए संविधान बनाया गया, जिससे आज देश चल रहा है, लेकिन देश में कुछ तानाशाही ताकतें संविधान को समाप्त करना चाहती हैं और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी।

भारत एक विचार है जो दुनिया को सीख देता है, जो महात्मा ने दिया, भगवान राम ने इंसानियत, मर्यादा की बात की वह भारत की है। भारत एक विचार है तो इसकी आत्मा कांग्रेस है, 140 साल से कांग्रेस पार्टी देश में कैसी भी परिस्थिति में रही, चुनाव हुये हारे भी जीते भी पर कांग्रेस के विचार कभी देश में समाप्त नहीं हुआ। देश में मजबूत और नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए संविधान कांग्रेस ने दिया। देश में संविधान को बचाना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। श्री चौधरी ने संघर्ष के साथ अपना जीवन जिया, सांसद, विधायक और मंत्री रहे, आज भी विधायक है और मप्र में लगातार दौरे कर रहैं हैं, वे अपनी राजनैतिक सोच को आगे बढ़ाते हुये संगठन को मजबूत कर रहे हैं।

बुंदेलखंड में यदि सबसे ज्यादा पलायन है तो उसका दोषी कौन हैं? बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे, शिक्षा सहीं नहीं, स्कूल नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं तो इसका दोषी कौन हैं। इसका दोषी 25 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह, मोहन यादव दोषी हैं।

नवागत कलेक्टर ने की कृषि विभाग की समीक्षा

जिले में दलहन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दे कृषि विभाग : कलेक्टर श्री गुप्ता

विदिशा (निप्र)। नवागत कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज 16 अप्रैल 2025 को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में कृषि विभाग के द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं योजनाओं के संचालन कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कृषि के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकासखंड विदिशा, ग्यारसपुर एवं नटेरन के समस्त कृषि अधिकारी उपस्थित थे तथा जिले के शेष विकासखंड यथा बासौदा, सिरोंज कुरवाई लटेरी के समस्त अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। उपसंचालक कृषि श्री केएस खपेड़िया ने जिले में संचालित की जा रही विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं द्वारा किए गए लक्ष्य एवं पूर्ति की जानकारी बैठक में दी गई तथा वर्ष 2025-26 हेतु लिए निर्धारित लक्ष्य की जानकारी से भी अवगत कराया गया। वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है, उससे जुड़ी प्लानिंग के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। चूंकि अभी रबी फसलों की कटाई का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। फसल कटाई के उपरांत मिट्टी के परीक्षण हेतु मिट्टी के नमूने लेने का सबसे उपयुक्त समय होता है इसीलिए श्री खपेड़िया ने उपस्थित जिले के समस्त कृषि अधिकारियों से किसानों को प्रेरित कर मिट्टी के नमूना लेने का आह्वान किया। दलहन क्षेत्र विस्तार, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे कृषि विभाग - कलेक्टर कृषि विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बताया कि देश में दलहन के खपत के मुकाबले उत्पादन कम है। अतः हमें दलहन फसलों जैसे मूंग , अरहर, उड़द, मसूर, चना आदि फसलों के बोनी का रकबा बढ़ाना चाहिए, जिससे दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ सके साथ ही ऐसी किस्म का चयन करना चाहिए जिससे प्रति हेक्टेयर दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। कृषकों को भी कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहकर नई किस्म की जानकारी प्राप्त कर उपयोग करना चाहिए। कृषि आदान सामग्री उपलब्धता की भी की समीक्षा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों हेतु आवश्यक आदान सामग्री जैसे बीज , उर्वरक (यूरिया, डीएपी आदि,) पौध संरक्षण दवा आदि की उपलब्धता एवं भंडारण की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए की किसी योजना का लाभ बार-बार एक ही परिवार को ना देते हुए पात्र समस्त हितग्राहियों को बारी-बारी से योजनाओं का लाभ दिया जाए। किसानों के हित में कार्य कर रहे किसान कॉल सेंटर आदि के जो टोल फ्री नंबर हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया भी मौजूद थे। उन्होंने पंचायत विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों में कृषि विभाग का समन्वय कर के कृषकों के लाभ हेतु कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कृषकों को कोई समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखें तथा समस्या आने पर शीघ्र निराकरण किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से महिलाओं के जीवन में आई खुशियां

रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का लाभ पाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही सशक्त भी हुई हैं। लाड़ली बहना योजना का लाभ पाकर महिलाओं के लिए जीवन में खुशियां आई हैं। यह कहना है रायसेन निवासी श्रीमती शकुन बाई का। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए श्रीमती शकुन बाई कहती हैं कि योजना के तहत हर महीने 1250 रू की राशि मिलने से उन्हें बच्चों की जरूरतें पूरी करने और छोटे-छोटे खर्चों में बहुत मदद हो जाती है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में से कुछ राशि हम बचा लेते हैं, जो हमारे आड़े वक्त में काम आएगा।

जिले की 247861 लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित की 30 करोड़ रू से अधिक राशि

रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा बुधवार को मण्डला जिले में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लाड़ली बहनों के बैंक खाते में अप्रैल माह की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा लाड़ली बहना योजना अंतर्गत रायसेन जिले की 247861 हितग्राही लाड़ली बहनों के खाते में कुल 30 करोड़ 27 लाख 76 हजार 850 रू की राशि अंतरित कि गई। मुख्यमंत्री डॉ यादव के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का रायसेन जिले की सभी ग्राम पंचायतों और निकायों में वर्चुअली लाईव प्रसारण देखा व सुना गया। आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रही है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हम जैसी जरूरतमंद महिलाओं के जीवन में आशा की नई किरण है। एक ओर यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है तो वहीं दूसरी ओर बहनों को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रही है। यह कहना है रायसेन जिले के ग्राम नांद निवासी लाड़ली बहना श्रीमती प्रीति मीणा का। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए वे कहती हैं कि योजना के तहत हर माह मिलने वाली धनराशि का उपयोग वह बच्चों के खिलौने और कॉपी-किताबों के लिए करती हैं। साथ ही घर की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी मदद हो जाती है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम देवगांव में किया बोरी बंधान

बैतूल (निप्र)। मप्र जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विकासखंड प्रभातपट्टन के ग्राम देवगांव में अंभोरा नदी पर बुधवार को बोरी बंधान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 बोरियों के उपयोग से नदी में बोरी बंधान किया गया, जिससे वर्धा डेम से परीक्षण के लिए छोड़े गए पानी को रोका जा सके। इस प्रयास का उद्देश्य नदी के बहाव को नियंत्रित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देना एवं जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना रहा। कार्यक्रम का संचालन विकासखंड समन्वयक सुश्री राधा बरोदे के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं तथा प्रस्फुटन समितियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर संभाग समन्वयक श्री कौशलेश तिवारी एवं जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी, जनपद सदस्य श्रीमती जयश्री पाटणकर, सरपंच बिसनुर श्रीमती प्रियंका ठाकरे, विभिन्न मेंटर्स एवं नवांकुर सदस्य उपस्थित रहे।

नवागत कलेक्टर श्री गुप्ता ने गंभीरता से सुनी आवेदिका की समस्या

आवेदन के निराकरण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)। नवागत कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सर्वप्रथम जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर आम नागरिकों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान जनसुनवाई में जनपद पंचायत विदिशा के ग्राम देहरी निवासी वयोवृद्ध महिला श्रीमती कोषा बाई ने आवास योजना से संबंधित समस्या सुनाते हुए बताया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में पात्रता सूची में नहीं जोड़ा गया है।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आवेदन को त्वरित संज्ञान में लेते हुए मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि आवेदिका के आवेदन का प्राथमिकता से निराकरण कराया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंची आवेदिका श्रीमती कोषा बाई को आश्वस्त कराया कि पात्रता की जांच कार्यों के उपरांत पात्रता की श्रेणी में होने पर उनका नाम आवास योजना की पात्रता सूची में दर्ज कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा तन्मयता से आवेदिका के आवेदन को संज्ञान में लेकर गंभीरता से समस्या सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश करने के फलस्वरुप आवेदिकाका श्रीमती कोषा बाई प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर रवाना हुई।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस दौरान आवेदिका श्रीमती कोषा बाई से संवाद कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना तहत प्रतिमाह राशि प्राप्त हो रही है या नहीं के संबंध में भी पूछताछ की। जिस पर महिला आवेदिका श्रीमती कोषा बाई ने हाजिर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें प्रतिमाह लाड़ली बहना योजना की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है। जिससे वह घर में नमक, मिर्ची, तेल, मसाला राशन इत्यादि के कार्यों में उपयोग करती हैं।

ईकेवाईसी कार्य में लापरवाही बरतने पर उचित मूल्य दुकानों पर की गई निलंबन की कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में विशेष अभियान चलाकर सभी राशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा टीएल बैठक में दिए गए निर्देशानुसार आष्टा एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा द्वारा राशन हितग्राहियों की इकेवाईसी के कार्य में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर आष्टा अनुभाग की 13 उचित मूल्य दुकानों से एक हजार रूपये की राशि आंशिक प्रतिभूति राशि के रूप में राजसात करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 02 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया है। एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा द्वारा आष्टा अनुभाग स्थित बरछापुरा, कन्नौदमिर्जी, बमूलिया, रायमल, श्यामपुरा, खजुरियाकासम, कजलास, सेमलीबारी, बीलपान, झिकडीमेवाती, अमरपुरा, सिध्दीकगंज सांगाखेडी, सैंधोखेडी की उचित मूल्य दुकानों पर एक हजार रूपये आंशिक प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही दो दुकानों खाचरोद एवं सिंगारचोरी को निलंबित कर निकट स्थित ग्राम पंचायत दुकान उदयपुर एवं झिकडीमेवाती से संलग्न किया गया है।

कलेक्टर ने एसडीएम और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया

विदिशा (निप्र)। नवागत कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज बुधवार की प्रातः विदिशा के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय भवन में पहुंचकर यहां संपादित किए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण। उन्होंने एसडीएम व तहसील कार्यालय भवन में संचालित कार्यों का अवलोकन ही नहीं किया बल्कि यहां उपस्थित स्टाफ से संवाद कर कार्यों को संपादन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी मौके पर दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में पहुंचने वाले आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो को दृष्टिगत रखते हुए उनकी समस्याओं व आवेदन का हल निकले और वह संतुष्टि जाहिर करें इसके लिए पहल करने के निर्देश समस्त स्टाफ को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय के बाहर रीडर और बाबू सहित अन्य स्टाफ के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा की जाए, ताकि आम नागरिकों को सहूलियतें हों।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में संचालित की जा रही अनेक गतिविधियां

सीहोर (निप्र)। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले मे 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में जल संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए दीवार लेखन, जागरूकता रैली, पोस्टर बैनर, ग्राम सभाएं, कलश यात्राएं सहित अनेकों गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

अभियान के तहत जिले के अनेक ग्रामों में कूप मरम्मत, तालाब जीर्णोद्धार, डैम की साफ-सफाई सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं तथा नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेत, तालाब, अमृत सरोवर, परकोलेशन टैंक, डगवेल, तालाब जीर्णोद्धार, जनभागीदारी के कार्य, कूप एवं बाउंड्री मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनभागीदारी से जल संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के अन्तर्गत समाज की भागीदारी तथा और विभिन्न सहयोगी विभागो की समेकित पहल से मुख्यत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, भूजल संवर्धन, पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार करना है। इसके साथ ही जल स्त्रोत में प्रदूषण कम करना, साफ सफाई करना, पौधरोपण के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण एवं जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जब भी अधिकारी गांव के भ्रमण पर जाएं तो ग्रामवासियों से जल उपलब्धता के बारे में पूछें : कलेक्टर

■ नरवाई जलाने पर जुर्माना लगाने और कार्रवाई के कलेक्टर ने दिए निर्देश

■ गौशालाओं एवं चारागाहों से हटाया जाए अतिक्रमण – कलेक्टर श्री बालागुरू के. ■ सभी राशन हितग्राहियों की 30 अप्रैल से पहले कराएं ईकेवाईसी : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा वाले विभागीय पत्रों और शासकीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण और त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में अपनी उच्च रैंक बनाए रखें। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि जनपद सीईओ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पीएचई विभाग सहित अन्य अधिकारी जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाए तो वे ग्रामवासियों से पेयजल की उपलब्धता, स्त्रोत और समस्या के बारे में पूछें और पेयजल की उपलब्धता न होने की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिन स्थानों पेयजल संकट की सूचना प्राप्त हो वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश आवश्यकतानुसार पेयजल का परिवहन किया जाए तथा निजी बोर भी अधिग्रहित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमाजन को पेयजल के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने बैठक में निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे तथा रेलवे सहित विभिन्न परियोजना के भू-अर्जन और मुआवजा वितरण का कार्य तेजी से करें, ताकि परियोजनाओं का काम जल्द शुरू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने वनग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाधिकार पट्टे धारकों के फौती नामांतरण की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए।

बैठक मे कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जिले के स्वीकृत लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए संबंधित अधिकारी शीघ्र भूखंड उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में संचालित गौशालाओं और चारागाहों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी विभाग अपनी संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि समग्र पोर्टल पर सभी नागरिकों की ईकेवाईसी का कार्य जल्द से जल्द से पूरा किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने सेवानिवृत्ति तथा पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि शासकीय कर्मचारियों के पेंशन तथा स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही समय सीमा में करें ताकि सेवा निवृत्त हुए शासकीय सेवक को समय पर पेंशन और शासकीय लाभ मिल सकें और उन्हें परेशान न होना पड़े। उन्होंने खाद्य अधिकारी को राशन का नियमित उठाव तथा शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने निर्देश दिए जिन गौशालाओं में अतिक्रमण है उनके अतिक्रमण हटाए जाएं। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने सभी सीएमओ तथा जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के जल्द से जल्द शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री नितिन टाले, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री जमील खान, श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री सुधीर कुशवाह सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

नरवाई जलाने पर की जाए कार्रवाई, लगाया जाए जुर्माना : कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में कहीं भी नरवाई न जलाई जाए तथा नरवाई जलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नरवाई जलाने पर छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 02 एकड़ से कम है उनपर 2500 रू प्रति घटना जुर्माना लगाया जाए।

इसी प्रकार 02 एकड़ से अधिक व 05 एकड़ से कम भूमि वालों पर 5000 रू प्रति घटना तथा 05 एकड़ से अधिक भूमि वाले भूमि मालिकों पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15000/-प्रति घटना जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नरवाई जलाने से खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति घट जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक जिले में विशेष अभियान चलाकर जिले के शेष रहे सभी हितग्राहियों की ईकेवाईसी कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो सेल्समैन ईकेवाईसी के कार्य में लापरवाही करें उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले के सभी हितग्राहियों से यह अपील की हैं कि वह अपनी ईकेवाईसी निर्धारित तिथि 30 अप्रैल से पहल कराएं, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ आगे भी प्रदान किया जा सके।

जलं गंगा संवर्धन अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन : बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को छोड़कर अन्य विभागों द्वारा जल संरक्षण की गतिविधियां आयोजित नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल विभाग के अधिकारियों को निर्देश कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जिले में शासन के निर्देशानुसार अभियान की सभी गतिविधियां संचालित की जाएं तथा इन गतिविधियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का अभियान है, सभी विभाग यह प्रयास करें कि इस अभियान की सभी गतिविधियों में अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने निर्देश दिए कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

॥ मंदिरम् ॥

86

रॉक कट गुफाओं में बैरावकोना का शिव मंदिर

इन शानदार एकल रॉक कट शिव दुर्गा मूर्तियों और गुफा को देखें। हमारे सनातनी पूर्वजों ने भावी पीढ़ियों के लिए हमारे प्राचीन इतिहास को हर एक पत्थर पर उकेरा है। ये गुफा मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी के भैरवकोना रॉककट गुफा शिव मंदिर, अंबावरम नल्लामाला हिल्स, आंध्र प्रदेश में हैं। भैरवकोण रॉक कट गुफा मंदिर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शैव परंपरा स्थल हैं। प्रत्येक मंदिर ब्रह्मा-विष्णु-शिव संयोजन प्रस्तुत करता है। सरस्वती-लक्ष्मी-पार्वती को भी एक ही चट्टान में उकेरा गया है। इन्हें नल्लामाला पहाड़ियों में एक ही चट्टान से उकेरा गया है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं जो आंध्र प्रदेश के उदयगिरि के विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थल के पास उत्तर-दक्षिण में फैली हुई हैं। इन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की उल्लेखनीय विशेषताएं शिलालेख और शिव के आठ अलग-अलग रूप हैं: 1)शशिनाग, 2)रुद्र, 3)विश्वेश्वर, 4)नागरिकेश्वर, 5)भार्गेश्वर, 6)रामेश्वर, 7)मल्लिकार्जुन और 8)पक्षमालिका लिंग। लिपि और प्रतिमा विज्ञान से पता चलता है कि चट्टानों को काटकर बनाया गया यह मंदिर 7वीं या 8वीं शताब्दी में बनाया गया था।

प्रमोशन की तैयारियों के बीच मांगी रिक्त पदों की जानकारी

विभाग प्रमुखों ने संभागीय अधिकारियों से मांगा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का ब्यौरा

भोपाल (नप्र)। मोहन यादव सरकार ने नौ साल से पेंडिंग कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए रास्ता निकालने के बाद पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मांगी है। यह जानकारी अप्रैल माह में ही देने के लिए कहा गया है।

इसी के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से एक हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि आने वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी क्षेत्री अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शासकीय कालेज में रिक्त पदों की संभागवार पूरी जानकारी मंगाकर शासन को भेजें। इसमें कालेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, नियमित, आकस्मिक निधि और आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है।

इस आधार पर देना होगी जानकारी

विभाग ने तृतीय श्रेणी कैडर के जिन पदों की जानकारी मांगी है उसमें हॉस्टल मैनेजर, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक कम लेखापाल और इससे नीचे के पद के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इनके वेतनमान की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में प्रयोगशाला परिचारक, फर्राश, बुक लिफ्टर और इससे नीचे की श्रेणी के पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। प्राचार्यों से कहा गया है कि वे पदों की जानकारी आईएफएमएस में उपलब्ध पदों की जानकारी के आधार पर परीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। अतिरिक्त संचालक संभाग स्तर पर जानकारी बुलवाने के बाद इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

जनजातीय कार्य विभाग ने इंजीनियरों को डेपुटेशन पर बुलाने लिया फैसला

उधर जनजातीय कार्य विभाग ने नई तकनीकी सेटअप के आधार पर रिक्त पदों की भरपाई का काम प्रतिनियुक्ति से करने का फैसला किया है। विभाग द्वारा शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों में भवन, सड़क निर्माण कार्य कर चुके इंजीनियरों की वरीयता के आधार पर अधीक्षण यंत्री सिविल के एक पद, कार्यपालन यंत्री सिविल के तीन पद, सहायक यंत्री सिविल के 14 पद और सहायक यंत्री विद्युत के 3 पदों पर पदस्थ कराने का निर्णय लिया है।

रेलवे ट्रैक पर फंसी बोलेरो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से टकराई

झांसी में कार सवार कूदकर भागे, दहशत में ट्रेन के रुकते ही यात्री नीचे उतरे

निवाड़ी (नप्र)। ग्वालियर से प्रयागराज जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर फंसी बोलेरो से टकरा गई। ट्रेन को आता देख कार सवार लोग कूदकर भाग निकले। ट्रेन के रुकने पर यात्री भी दहशत में आ गए। वे नीचे उतर गए। इससे करीब 35 मिनट तक ट्रेन प्रभावित रही।

हादसा बुधवार-गुरुवार दरमियानी रात 1 बजे झांसी मंडल में हुआ। यहां मगरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक कार पटरी पार कर रही थी। इसी दौरान फंस गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, लेकिन कार इंजन के चपेट में आ गई।

शादी समारोह से लौट रहा था परिवार- हादसे की जानकारी लगते ही आरपीएफ व जीआरपी कर्मी भी पहुंच गए। थोड़ी देर में रेल अफसर भी पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह क्षतिग्रस्त बोलरो को पटरी से हटाया जा सका। हादसे के बाद बोलरो सवार वहां नहीं मिले। जीआरपी कर्मी उनकी तलाश कर रहे हैं। कार में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे।

पुराना अंडरब्रिज बंद होने से हादसे- ट्रेन से कार के टकराने की घटना यूपी-एमपी के बॉर्डर पर हुई है। यहां नया अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके चलते पुराना अंडरब्रिज बंद कर दिया है। रेलवे ने आने-जाने वाले लोगों के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया है। इससे अड़जार, मगरपुर, देवरी ,बहेरा समेत करीब 10 किमी इलाके में बसे गांवों के ग्रामीण सीधे पटरी पार कर रहे हैं। कई जगह से लोग अपने वाहन भी पत्थर लगाकर पार कराते हैं।

भोपाल में ब्रिज के नीचे कब्जों पर चला बुलडोजर

एक दर्जन अवैध दुकानें हटाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मुबारकपुर चौराहे पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। यहां से एक दर्जन दुकानों को हटाया। हंगामा न हो, इसलिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

तहसीलदार नरेंद्र परमार ने बताया कि मुबारकपुर चौराहे पर ब्रिज के नीचे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इन्हें हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद दुकानें नहीं हटाई गई। इसलिए गुरुवार को पुलिस और नगर निगम के अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया गया। टीन शेड की दुकानों के साथ अलग से भी शेड बना दिए गए थे, इन्हें भी हटाया गया।

टीन शेड की दुकानें, रेस्टोरेंट का संचालन भी- ब्रिज के नीचे कई लोगों ने टीन शेड की दुकानें बना रखी थी। जहां रेस्टोरेंट, कैफे आदि का संचालन हो रहा था। हंगामे की आशंका थी। इसलिए खासा पुलिस बल मौजूद रहा।

भोपाल सहित 10 जिलों में हुई मॉक ड्रिल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज (17 अप्रैल) भोपाल सहित प्रदेश के 10 जिलों में रासायनिक औद्योगिक आपदा पर मॉक अभ्यास आयोजित किया । यह अभ्यास सुबह 9:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चला।

यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने किया जाएगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी लाखन सिंह चौधरी ने बताया कि, यह मॉक अभ्यास सिर्फ एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। जिसे आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों की तैयारी को परखने के लिए किया जा रहा है।जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल एक मॉक अभ्यास है, कोई वास्तविक आपदा नहीं।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया।

मप्र हाउसिंग बोर्ड की चीफ अकाउंट ऑफिसर को हटाया

लोकायुक्त में की जा चुकी शिकायत ओझा पर बोर्ड को नुकसान के आरोप

भोपाल (नप्र)। एमपी हाउसिंग बोर्ड की चीफ अकाउंट अफसर अल्पना ओझा को गुरुवार को पद से हटा दिया गया। उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। जिसमें बोर्ड को करीब डेढ़ करोड़ रुपए का नुकसान कराने का आरोप लगा था।

वित्त विभाग, मप्र शासन ने गुरुवार को सिंगल ऑर्डर जारी किया। अल्पना को संयुक्त संचालक कार्यालय, कोष एवं लेखा में अटैच किया गया है। उन पर निर्माण कार्यों के बिल लटकाने और कमीशन मांगने के लगातार आरोप लग रहे थे।

लोकायुक्त में की गई थी शिकायत- पिछले साल दिसंबर में ओझा की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। एंटी करप्शन आर्गेनाइजेशन के शिवशंकर दास ने यह शिकायत की थी। लोकायुक्त ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर और सचिव से इस मामले में पत्र लिखकर जवाब मांगा था।

एक और जांच चल रही- हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह ने भी दिसंबर में कुछ निर्माण कार्यों के भुगतान नहीं होने के लिए पत्र लिखा था। इनमें रीवा जिले के रहट में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं देवगांव, नोढिया, शिवराजपुर, बिछरहटा, खटखरी में आवास गृहों एवं आयुष आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण संबंधित भुगतान था।

ब्राजील के खेतों में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान

मैकेनाइज्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मक्का हार्वेस्टर और सोयाबीन प्रोडक्शन प्लांट भी देखा

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक के लिए ब्राजील के दौरे पर हैं। शिवराज ने ब्राजील में टमाटर के खेतों में पहुंचकर मैकेनाइज्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से होने वाली सिंचाई की तकनीक को देखा। शिवराज ने ब्राजील कृषि मंत्रालय के अफसरों के साथ सोयाबीन प्रोडक्शन प्लांट पहुंचकर निरीक्षण किया।

शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों सहित कुछ अन्य संस्थानों का दौरा किया। शिवराज सिंह ने ब्राजील में, खेती में अपनाई जा रही मैकेनाइजेशन और इरिगेशन की अत्याधुनिक पद्धतियों का अवलोकन करने के साथ ही हमारे किसान भाइयों-बहनों के दृष्टिकोण से समझा कि भारतीय किसानों को नई पद्धतियों से और किस तरह लाभ पहुंचाया जा सकता है।

टमाटर के खेतों में मैकेनाइज्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को देखने के बाद कहा-यहां आकर मैं खेती देख रहा हूं और यहां से सीख भी रहा हूं और भारत में हम कैसे हम मिलकर इस दिशा में खेती को आगे ले जा सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, उस दिशा में भी प्रयत्न करेंगे। टमाटर के फॉर्म में कृषि मंत्री जी के साथ,

टमाटर की खेती सहित यहां के सिंचाई के सिस्टम को देखा है। एक मशीन है, उसमें यूरिया का टैंक है, वो पानी में घोला जा रहा है और पानी में घोलकर पाइपलाइन के जरिए, इसमें स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इन स्प्रिंकलर से टमाटर में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। जितनी जरूरत है, उतना ही पानी दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। साथ में पानी का टैंक बनाया है, उस टैंक से यह पानी लेकर आते हैं। वर्षा में उसमें जल इकट्ठा होता है और उस पानी को यहां स्प्रिंकलर जैसी जो रचना बनी है, उसमें देते हैं ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सके और पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम है। जितना पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए और जितना पानी चाहिए, उतना ही पानी जाता है।

ब्राजील से प्रतिनिधिमंडल आकर सारी संभावनाएं तलाशें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि के और तेजी से विकास के लिए मैंने आमंत्रित किया है कि ब्राजील से भी प्रतिनिधिमंडल आए और सारी संभावनाओं को तलाशे। भारत से भी पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा विश्वास है कि दोनों देश, यहां की बिजनेस कम्युनिटी भी प्रभावी ढंग से फिर भारत के साथ व्यापार, टेक्नॉलाजी इत्यादि बढ़ाने पर गंभीरता से न केवल विचार करेगी, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगी।

टमाटर के साथ कॉर्न की भी खेती देखी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राजील के कृषि मंत्री के साथ ब्राजील में टमाटर के फार्म हाउस पर भी पहुंचे, जहां हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है। शिवराज सिंह ने कहा मैंने यहां कॉर्न की खेती देखी, आफ्टर टमाटर की खेती और यह भी वैराइटीज अलग-अलग हैं। एक वैरायटी में वायरस अटैक है, दूसरी वैरायटी सेफ है।

मैकेनाइजेशन ब्राजील ने पूरी तरह से किया हुआ है और कॉर्न के बारे में मुझे बताया कि 22 टन पर हेक्टर यहां ईल्ड है, जो वास्तव में बहुत अचरज में डालने वाली है और सारा सिस्टम मैकेनाइज है। इरिगेशन का सिस्टम भी जिस ढंग से पानी देते हैं, वह भी मैं देखा, वह भी अद्भुत है।

आईसीएआर के साथ मिलकर और अच्छे बीजों का विकास संभव

शिवराज सिंह ने बताया कि मैंने प्रेजेंटेशन देखा है। अगर कपास को चुनना भी है तो सीधे हार्वेस्टर से निकालते हैं। जो रिसर्च और शोध यहां चल रहे हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर करें कि हम और अच्छे बीज कैसे हम बना सकें। उन्होंने बताया कि कई विषयों पर चर्चा हुई है। भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की भी, और मिलकर तय किया है कि इन सारी संभावनाओं का दोहन करेंगे।

प्रदेश के 9 शहरों में पारा 40 डिग्री पार

तेज धूप से बचने भोपाल में छाते निकले, इंदौर में टेंट के नीचे निकल रही बारातें

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में ओले-बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही गर्मी का असर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में धूप से बचने के लिए छाते निकल गए हैं। इंदौर में टेंट के नीचे बारातें निकल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर-उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोपहर में लोग बेहद जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सड़कें लगभग सूनी हो गई।

प्रदेश के 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इनमें रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, नरसिंहपुर, उज्जैन, धार और गुना शामिल हैं। सबसे गर्म रतलाम रहा। जहां तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में 41.6 डिग्री, खंडवा में 41.5 डिग्री, शाजापुर में 41.1 डिग्री और खंडवा-नरसिंहपुर में पारा 41 डिग्री रहा। उज्जैन में 40.7 डिग्री, धार में 40.4 डिग्री और गुना में पारा 40.3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्से में गर्मी का असर दिखा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी पारे में बढ़ोतरी हो सकती है।

धार-पांढुर्णा में तेज बारिश का दौर- प्रदेश में गर्मी के साथ बारिश का दौर भी रहा। धार के मनावर में शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं, पांढुर्णा में भी पानी गिरा। रात में खरगोन, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में भी मौसम बदला रहा।

आज रहेगा तेज गर्मी वाला मौसम- मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया, 18 अप्रैल तक तेज गर्मी की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

अवैध रेत की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मारी, नाबालिग की मौत

प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप ; परिजन बोले- पुलिसवालों की कॉल डिटेल चेक करें

मुरैना (नप्र)। मुरैना के देवगढ़ में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 15 साल के लड़के को टक्कर मार दी। हादसे में नाबालिग की मौत हो गई। चालक फरार हो गया। गुस्साए परिजन और ग्रामीण शव सड़क पर लेकर बैठे गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के समझाने पर वे करीब 6 घंटे बाद माने और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

परिजन का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रेत खनन का कारोबार पुलिस और माफिया की मिलीभगत से चल रहा है। उनकी मांग है कि देवगढ़ और बागचीनी थाना प्रभारियों समेत अन्य पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल निकाली जाए। साथ ही अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी ट्रैक्टर चालक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जाए।

मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। इधर, एसपी समीर सौरभ ने क्राइम

ब्रांच सहित तीन पुलिस की टीमें ट्रैक्टर और आरोपी चालक को पकड़ने के लिए भेजी है। जौरा एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया, आरोपी की पहचान कर ली है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

दादा के रोकने पर स्पीड बढ़ाकर भागा चालक- जानकारी के अनुसार, हादसा आज गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। बावड़ी गांव निवासी छोटू भदौरिया (15) साइकिल से बागचीनी बाजार सामान खरीदने निकला था। उसके पीछे दादा कप्तान सिंह भदौरिया भी पैदल चल रहे थे। नील मंदिर के पास अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने छोटू को टक्कर मार दी। दादा ने चिल्लाकर ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। तभी चालक स्पीड तेज कर मौके से भाग निकला।

सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी चालक- बागचीनी चौराहे पर लगे सीसीटीवी में आरोपी ट्रैक्टर चालक कैद हुआ है। ट्रैक्टर-ट्रॉली काफी तेज दौड़ाते हुए ले जा रहा है।

कांग्रेस बोली- पुलिस की अवैध रेत कारोबार में पार्टनरशिप

कांग्रेस कार्यकर्ता उदयवीर सिंह सिकरवार ने कहा, यह रोज की घटना है। 15 दिन पहले भी पठानपुरा में एक्सीडेंट में घायल लड़का अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। खारोली में भी ऐसी घटना हुई। दोनों थानों की पुलिस हर ट्रैक्टर ट्रॉली से 5 हजार रुपए लेती है। माफिया बेखौफ ट्रैक्टर स्पीड में दौड़ाते हैं। दोनों थानों के दरोगा की कॉल डिटेल निकालोगे तो अभी पता चल जाएगा कि कौन से ट्रैक्टर ने कुचला है। पुलिसकर्मियों पार्टनरशिप में खुद के रेत के अवैध ट्रैक्टर चला रहे हैं।